

अंक-1
मई 2021
www.rgfindia.org



सद्भावना

संग्रह

राजीव गांधी स्मारिका

21 मई 2021

भारत राष्ट्रीय
मानवाधिकार
आयोग (NHRC)
की रिपोर्ट

दिल में जलें चिताएँ
उबरें कैसे इनसे?



सदभावना संग्रह

अंक 1, 21 मई 2021

अनुक्रमणिका

संपादकीय.....	1
मुद्दा 1 - हम पृथ्वी पर अपने आवासीय उद्देश्य को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए स्वयं को उससे कैसे जोड़ सकते हैं?	4
संपादक का एक व्यक्तिगत वक्तव्य	4
राजीव गांधी को याद करते हुए 21 मई 2021	5
मुद्दा 2 - हम दूसरे इंसानों से बेहतर तरीके से कैसे सम्बद्ध हो सकते हैं?	6
मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणापत्र	6
कुछ अंश - चीन में मानवाधिकारों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2020.....	11
स्वायत्त क्षेत्र : झिंजियांग, तिब्बत और भीतरी मंगोलिया	12
हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र.....	14
मानवाधिकारों का चीनी आधिकारिक संस्करण	15
कुछ अंश : भारत में मानवाधिकारों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2020	17
भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की रिपोर्ट	22
अंतरमन का गणराज्य- Seamus Heaney की कविता	1
(Republic of Conscience – Poem by Seamus Heaney)	Error! Bookmark not defined.
मुद्दा 3 - हम बेहतर तरीके से इंसानों को प्रकृति से कैसे जोड़ सकते हैं?	3
UN HRC संकल्प 46/7... मानवाधिकार और पर्यावरण.....	3
मेरे दोस्त का जवाब, हवा में उड़ रहा है :	9
COVID-19 की दूसरी विनाशकारी लहर.....	16
दिल में जलें चिताएँ.....	17
गंगा के तट पर बेशुमार लाशें	19
पारुल खाकर की गुजराती में कविता : शववाहिनी गंगा	20
इलियास शेख द्वारा हिंदी अनुवाद	20
मुद्दा -1 पर लौटें- हम इस समय में खुद से कैसे संबंधित हैं?	21
इन सब से कैसे उबरें? संगीत और कविता की उपचार शक्ति का प्रयोग करें :	21
ओ नोदि रे एकती कोथा शुधाई, बांग्ला गीत फिल्म सिद्धार्थ से	21
ओ गंगा आमार माँ, भूपेन हजारिका द्वारा गाया गया	22
७०७७ (गंगा) मधुसूदनन नायर की कविता मलयालम में.....	22
नदियाँ कार्तिकेय खेत्रपाल द्वारा और केदारनाथ सिंह द्वारा पाठ किया गया.....	22
या, हम अपने प्राचीन काल के ज्ञान के लिए गहरी खुदाई कर सकते हैं : स्नान मंत्र	22
स्वामी सानंद : भविष्य द्रष्टा, सिद्ध पुरुष, जिन्होंने गंगा को बचाने के लिए मौत का उपवास किया.....	23
श्री सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धांजलि : 9 जनवरी 1927 - 21 मई 2021	25

संपादकीय

इतिहास में कुछ ही क्षण ऐसे आते हैं, जिनका आज हम सामना कर रहे हैं। हम नीति और शासन, बजट और नौकरियों, प्रलोभनों व अधिनियमों की तुलना में कहीं अधिक मौलिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमें यह परिभाषित करने के लिए चुनौती दी जा रही है कि हमारे लिए यह ग्रह और इसकी संकीर्ण मानव निर्मित इकाइयाँ - जैसे समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी - बनाने का क्या तुक है जो सभी के लिए काम करती हैं।

और "हमें" यह याद रखना चाहिए कि हम "सभी" केवल 7 अरब मनुष्य नहीं हैं, अपितु एक-दूसरे पर निर्भर विविधताओं से भरी लाखों जीवित प्रजातियों, जीवाणुओं व निर्जीव वस्तुओं - पहाड़, चट्टानें, जल निकाय, नदियों - में अविश्वसनीय रूप से एक जाति भर हैं जो सबसे जिंदादिल इंसानों से ज़्यादा जीवंत हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मानव जाति को यह बताने की जरूरत है कि उसने अपनी डेढ़ जीबी मानव पीढ़ी की संभावित विकासवादी श्रेष्ठता के साथ क्या किया है। इससे पहले कि आरएनए के 32 केबी की अकेली तार, एन-कोरोना वायरस-2019, द्वारा उसका नामोनिशान मिटा दिया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो, प्रकृति बार-बार बाढ़, जंगल की आग, चक्रवात, भूकंप और निःसंदेह विश्वव्यापी महामारी के रूप में अपने गुस्से का इज़हार कर रही है।

इसलिए हमें एक साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण जीवन के इस मसले पर विचार करना होगा। हमने प्राचीन काल में जो कुछ भी सीखा है - उसपर दोबारा मंथन करना होगा। हमें अधिकतम संख्या की भलाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की अपनी प्रचलित आदत को बदलना होगा जो स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में हालात से समझौता करने को बाध्य करती है। हमने गांधी के ताबीज़ पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और हम केवल उस अंतिम व्यक्ति (अंत्योदय) तक सहायता पहुँचाने के लिए तत्पर क्यों नहीं हुए?

हमने हवसिए पूँजीवाद द्वारा संचालित अंधाधुंध भागती तकनीक को, समाज की कीमत पर अपनाकर, बिना सोचे-समझे क्यों जगह दी! - जबकि हम जानते थे कि इसे आत्मसात करने में कठिनाइयाँ हैं और अपने ग्रह पर इन सबके बुरे प्रभाव पड़ते हैं!! हम "वसुधैव कुटुम्बकम्" के ज्ञान को कैसे भूल गए!! "सारी सृष्टि एक परिवार है" - इसे मानने के बजाय हमने ग्रह पर कब्जा कर लिया और वह भी कुछ के लिए ही उसे हजम किया; इन कुछ में सभी मनुष्य भी नहीं? सात पीढ़ियों की बौद्धिक विरासत की उपेक्षाकर हमने अमेरिका मूलक ज्ञान को तरजीह दी? हमने राज्य पूँजीवाद जैसी तुच्छ चीज़ के लिए संतुलनपरक यिन-यांग सिद्धांत¹ को क्यों छोड़ दिया?

अंततः हमने अपने व्यक्तिगत आचरण में पुरुषार्थ चतुष्टय - धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के संतुलित लक्ष्यों को क्यों विस्मृत कर दिया, जो बड़ी सहजता से एक से दूसरे में प्रवेश करने की व्यवस्था देते हैं, जिससे हम अपने जीवन-चक्र को लाँघते आए थे? अद्वैत निष्कर्ष "अहम् ब्रह्मास्मि" की सरल विशालता को कैसे भूल गए? यदि मैं ब्रह्म हूँ तो हम सब एक हैं!

¹ यिन-यांग सिद्धांत : यिन और यांग चीनी संस्कृति में एक जटिल, संबंधपरक अवधारणा है जो हजारों वर्षों में विकसित हुई है। संक्षेप में, यिन और यांग का अर्थ यह है कि ब्रह्मांड एक वैश्विक द्वंद्व द्वारा नियंत्रित होता है, दो विरोधी और पूरक सिद्धांतों या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के समुच्चय, जिन्हें प्रकृति में देखा जा सकता है।

अथवा, बुद्ध द्वारा दिखाए अष्टांगिक मार्ग के सम्यक् सिद्धांत, या फिर इब्राहीमी धर्मों² द्वारा निर्देशित सार्वभौमिक प्रेम और करुणा का मार्ग? – बजाय इनके, जैसा कि एलियट ने कहा, हम "हमारी वीरता से अप्राकृतिक दोषों को जन्म देते हैं", हम आदर्शवाद के नाम पर मानवता के खिलाफ अपराध करते हुए सुपरमैन बनते जा रहे हैं। हम पिछले 100 वर्षों में हिटलर से पोल पॉट³ तक की परेड के साक्षी हैं।

इसलिए इस अंक से हम सद्भावना संग्रह नामक एक विस्तृत प्रारूप, बहु-दृष्टिकोण, मल्टी-मीडिया प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। इसके प्रत्येक अंक में केवल तीन विषयों पर लेख होंगे —

विषय 1 - हम मनुष्य जन्म के उद्देश्य को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए स्वयं को कैसे विकसित कर सकते हैं?⁴

विषय 2 - हम दूसरे इंसानों से बेहतर तरीके से कैसे सम्बद्ध हो सकते हैं? और,

विषय 3 - हम बेहतर तरीके से इंसानों को प्रकृति से कैसे जोड़ सकते हैं?

पहले अंक में लेख/ कविता/ संगीत (in embedded weblinks) के चार सेट हैं, और प्रत्येक विषय पर एक सेट है और अब हम पहले विषय पर लौट रहे हैं।

पहला विषय संपादक के अपने व्यक्तिगत बयान से शुरू होता है। इसके बाद हम आज स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि के रूप में एक संक्षिप्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वह शांति और सुलह के एक महान पैरोकार थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित घरेलू शांति समझौतों जैसे - पंजाब समझौता, असम समझौता और मिजोरम समझौता पर हस्ताक्षर किए। राजीव जी ने 1991 में सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सद्भावना यात्रा का भी आयोजन किया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने शांति और निरस्त्रीकरण की वकालत की थी और 1962 में जन्मी शत्रुता के बाद भी 1988 में चीन का दौरा किया। परन्तु विडंबना यह रही कि श्रीलंका में शांति लाने के उनके प्रयासों से उनकी जान चली गई, क्योंकि कट्टर चरमपंथी समूह शांति नहीं चाहते थे।

² इब्राहीमी धर्म : *इब्राहीमी धर्म* उन धर्मों को कहते हैं जो एक ईश्वर को मानते हैं एवं अब्राहम को ईश्वर का पैगम्बर (संदेशवाहक) मानते हैं। इनमें यहूदी, ईसाई, इस्लाम और बहाई धर्म आदि शामिल हैं। ये धर्म मध्य पूर्व में पनपे थे और एकेश्वरवादी हैं।

³ पोल पॉट (Pol Pot) : कम्बोडियाई साम्यवादी आंदोलन के नेता और 1976-1979 के मध्य लोकतांत्रिक कम्पूचिया के प्रधानमंत्री थे। कंबोडिया नेता के रूप में खुद के देश को शुद्ध करने के प्रयास में अनुमानतः 17 से 25 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पोल पॉट 1975 के मध्य में कंबोडिया के नेता बने। अपने सत्ताकाल के दौरान, पॉट ने "सभ्यता पुनरुत्थान" के उद्देश्य से कृषि सामूहीकरण का एक संस्करण लागू किया, जिसके अंतर्गत शहरी निवासियों को ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित कर उन्हें सामूहिक खेतों और बेगार परियोजनाओं में काम करने के लिए बाध्य किया गया। इस दास श्रम, कुपोषण, खराब चिकित्सा सेवाओं के संयुक्त प्रभाव और मृत्युदंड के चलते कम्बोडिया की लगभग 21% जनसंख्या काल का ग्रास बन गयी।

⁴ Residence on Earth (Spanish: Residencia en la Tierra): चिली के कवि Pablo Neruda की कविता की किताब है। रेसिडेंस ऑन अर्थ तीन खंडों में 1933, 1935, और 1947 में प्रकाशित हुआ था। Neruda ने 1925 से 1945 तक दो दशकों की अवधि में पुस्तक लिखीं। यहाँ जीवन-पुष्टि करने वाली पंक्तियाँ हैं, जो इसी नाम से Pablo Neruda की दो कविताओं में मिश्रित हैं।

"क्या आप मानव के पदचिह्नों में निरंतर समय की जीत नहीं सुनते हैं... शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है...जब हमें सब कुछ मरा हुआ सा लगता है, और बाद में जीवित साबित होता है।"

दूसरा विषय इस बार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है, जो एक हजार बार भंग होने के बावजूद, भी मानवता का सबसे मजबूत बयान और संस्थागत तंत्र बना हुआ है कि हम खुद से कैसे सम्बद्ध हैं? हम आयरिश कवि नोबेल पुरस्कार विजेता श्री सीमस हेनी के रिपब्लिक ऑफ कॉन्शियस के संपादक द्वारा सस्वर पाठ की एक ऑडियो फ़ाइल शामिल कर रहे हैं, जिसे उन्होंने विशेष रूप से सार्वभौमिक घोषणा की 25 वीं वर्षगांठ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के निमंत्रण पर लिखा था। उसके बाद हम "वास्तविक दुनिया" - राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्रोतों का उपयोग करते हुए चीन और भारत में मानवाधिकार की स्थिति को देखेंगे।

तीसरा विषय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 23 मार्च, 2021 के संकल्प के साथ शुरू होता है, जो पर्यावरण और मानवाधिकारों से संबंधित है। इसमें RGICS Fellow, जीत सिंह का एक लेख भी है, जो COVID-19 जैसे पशुजन्य रोगों पर 20 वर्षों से अधिक हुए शोध कार्यों का हवाला देता है, जिसमें कहा गया है कि बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षरण और मनुष्यों द्वारा अन्य प्रजातियों का विनाश इनके आगमन का कारण है।

हम पहले विषय COVID की दूसरी लहर की समकालीन वास्तविकता और इसके लपेटे से निपटने पर लौटते हैं। हमने इसमें जीवन और मृत्यु के रूपक के रूप में गंगा नदी का उपयोग करते हुए, स्वयं और प्रकृति के बारे में कई कविताएँ और गीत संजोये हैं।

हमें उम्मीद है, कि आप सदभावना संग्रह के इस नए प्रारूप का आनंद लेंगे।

मुद्दा 1 - हम मनुष्य जन्म के उद्देश्य को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए स्वयं को कैसे विकसित कर सकते हैं?

संपादक का एक व्यक्तिगत वक्तव्य

एक सप्ताह पहले मैं अस्पताल से चार सप्ताह के बाद घर वापस आया। मुझे 16 अप्रैल को फेफड़ों में गंभीर संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था। मैं अब भगवान की कृपा से ठीक हो रहा हूँ! मैं अपने सभी शुभचिंतकों और परिवार के सदस्यों के सहयोग और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ। परन्तु मेरे लिए अभी सातों दिन चौबीसों घंटे बाहरी ऑक्सीजन की व्यवस्था घर पर ही की गई है।

खैर, मैं इस सब से बाहर निकल कर इस बात की पुष्टि करने के लिए आया हूँ कि जिस ब्रह्मांड में हम पैदा हुए हैं, वह "अव्यवस्थित" है। इसलिए मानव जीवन का चमत्कार और उद्देश्य ब्रह्मांड के एक हिस्से में "व्यवस्था" लाना है, चाहे वह कितना ही छोटी क्यों न हो। यह व्यवस्था कुछ भी हो सकती है जो प्राकृतिक घटनाओं व मानव व्यवहार से संबद्ध मानवीय समझ को बढ़ाती है। जो संघर्ष को कम करती है, और शांति निर्मित करती है, और प्यार फैलाती है, और सौंदर्य व आनंद पैदा करती है। दूसरे शब्दों में, यही सद्भावना है।

ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम हालाँकि हमें यह सिखाता है, कि ब्रह्मांड के हमारे छोटे से हिस्से में X इकाइयों को व्यवस्थित करने में, हम हमेशा कहीं और Y इकाइयाँ को अव्यवस्थित करना पड़ता है और $Y > X$, अर्थात् y बड़ी है x से, जिससे अंत में अव्यवस्थिता बढ़ जाती है। यह प्रकृति का एन्ट्रॉपी नियम है। (जैसे कि हम एक कमरे को ठंडा करने के लिए एसी कमरे के बाहर एसी से अधिक गर्मी पैदा करते हैं।)

तो क्या इस नियम के बावजूद हम सद्भावना के छोटे-छोटे दिए जलाते रहे ? हमारे – जहाँ हम संगीत साजते हैं, फिल्म बनाते हैं अथवा कविता व नाटक लिखते हैं, अपनी विकृतियों की पुनर्व्याख्या करते हैं, या नीति आलोचना में संलग्न हो ऐसे सबक लेते हैं, जिन्हें शक्तिशाली लोगों द्वारा अनदेखा किया जाता है, या गरीबों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना स्थापित करते हैं भले ही हर दिन वे और अधिक गरीब होते जा रहे हैं?

यहाँ मेरा जवाब दो कारणों से पक्का हाँ है, एक मामूली कारण है और एक व्यापक कारण है। मामूली कारण यह है कि अगर हम अभी भी सद्भावना बनाने पर काम नहीं करते हैं, तो हम बहुत कुछ अनिष्ट ही करेंगे, इसलिए इसे पहले से बेहतर करना है।

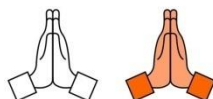
व्यापक कारण यह है कि जीवन और इसे बनाने वाले डीएनए अणु जैसे खंड, अथाह ब्रह्मांड की अनियमितता से उभरने वाली एक ऐसी अप्रत्याशित घटना है, जिसने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया, ऐसा लगता है जैसे उसने ब्रह्मांड के आग्रह को नहीं सुना। इसलिए हमें यथासंभव सद्भावना बनानी चाहिए। क्षमा करें, भावनाओं में बह गया! ऐसा तब होता है जब आप चार हफ्ते से पीठ के बल लेटे हों!! सभी को शुभकामनाएँ!

स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को याद करते हुए - 21 मई 2021

"राष्ट्र निर्माण का लोकतांत्रिक तरीका धैर्य, दृढ़ता और सुलह की भावना है ..." "यदि आप जिस चीज में भरोसा करते हैं उसके लिए मर-मिटने की बात आती है, तो मुझे संकोच नहीं है।"



पंचायती राज और संचार क्रांति के जनक, आधुनिक सोच रखने वाले व युवा भारत की परिकल्पना करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री **भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी** की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन!!



राजीव जी की सद्भावना यात्रा पर एक लघु वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

<https://www.youtube.com/watch?v=FDA8YHtP9d4>

मुद्दा 2 - हम दूसरे इंसानों से बेहतर तरीके से कैसे सम्बद्ध हो सकते हैं?

इस विषय पर, शायद एक भी दस्तावेज इतना विस्तृत और बेहतरीन नहीं है जिन्हें मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणाओं का आदर्श ठहराया जाए जितना कि व्यवहार में इसका उल्लंघन हुआ है। इसलिए हम 72 साल पुराने इस दस्तावेज की जाँच शुरू करते हैं।

मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणापत्र

10 दिसंबर, 1948 में अपनाए गए, घोषणापत्र के सार-संक्षेप में कहा गया है :

हर जगह सभी लोगों के समान मानवाधिकार हैं जिन्हें कोई नहीं छीन सकता। यह दुनिया में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार है। यह घोषणा सभी लोगों के गरिमा और मूल्य, तथा महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों की पुष्टि करती है। यहाँ वर्णित अधिकार हर जगह सभी लोगों के लिए समान रूप से मान्य हैं।

लेकिन इस समय में हमें एक-एक आलेख को पढ़ना चाहिए, जो कि कुल 30 हैं।

प्रस्तावना

जबकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान अविच्छेद्य अधिकारों की मान्यता दुनिया में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है।

जबकि मानवाधिकारों की अवहेलना और अवमानना के परिणामस्वरूप बर्बर कार्य हुए हैं, जिन्होंने मानव जाति की अंतरात्मा को ठेस पहुँचाई है, जिसमें एक ऐसी दुनिया का आगमन हुआ है और एक ऐसी दुनिया का आगमन जिसमें मनुष्य को भाषण और विश्वास की स्वतंत्रता और भय और अभाव से मुक्ति का आनंद मिलेगा, आम लोगों की सर्वोच्च आकांक्षा के रूप में घोषित किया गया है।

जबकि यह आवश्यक है कि यदि मनुष्य को अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोह के अंतिम उपाय के रूप में सहारा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना है, तो मानव अधिकारों की रक्षा कानून के शासन द्वारा की जानी चाहिए।

जबकि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है।

जबकि संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने घोषणा पत्र में मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य में मौलिक मानव अधिकारों में अपने विश्वास की पुष्टि की है, और पुरुषों एवं महिलाओं के समान अधिकार और बड़ी आज़ादी में सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प किया है।

मानव अधिकारों की इस सार्वभौम घोषणा को सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि के एक सामान्य मानक के रूप में घोषित करता है, अंत तक कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग, इस घोषणा को लगातार ध्यान में रखते हुए, इन के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण और शिक्षा द्वारा प्रयास करेगा। अधिकारों और स्वतंत्रताओं और प्रगतिशील उपायों द्वारा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, उनकी सार्वभौमिक और प्रभावी मान्यता और दोनों सदस्य राज्यों के लोगों के बीच और उनके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों के लोगों के बीच पालन को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे।

आलेख 1

सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं तथा सम्मान और अधिकारों में समान होते हैं। वे तर्क विवेक से संपन्न होते हैं, और उन्हें भाईचारे की भावना से एक दूसरे के प्रति कार्य करना चाहिए।

आलेख 2

जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म, या अन्य स्थिति जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, हर कोई इस घोषणा में उल्लिखित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है। इसके अलावा, देश या क्षेत्र की राजनीतिक, क्षेत्राधिकार, या अंतरराष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, चाहे वह स्वतंत्र हो, विश्वास हो, गैर-स्वशासी हो या संप्रभुता की किसी अन्य सीमा के तहत हो।

आलेख 3

प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है।

आलेख 4

किसी को भी गुलाम या दास बनाकर नहीं रखा जाएगा; गुलामी और दास व्यापार अपने सभी रूपों में प्रतिबंधित किया जाएगा।

आलेख 5

किसी को भी यातना अथवा क्रूर, अमानवीय/ अपमानजनक व्यवहार दंड के अधीन नहीं दिया जाएगा।

आलेख 6

हर व्यक्ति को हर जगह कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है।

आलेख 7

कानून के समक्ष सभी एक समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। इस घोषणा के उल्लंघन में किसी भी भेदभाव के खिलाफ और इस तरह के भेदभाव के लिए किसी भी उत्तेजना के खिलाफ सभी समान सुरक्षा के हकदार हैं।

आलेख 8

प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों के लिए सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रभावी सजा का अधिकार है।

आलेख 9

किसी को भी मनमाना गिरफ्तार, नजरबंद या निर्वासित नहीं किया जाएगा।

आलेख 10

प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण और उसके खिलाफ किसी भी अपराधिक आरोप के निर्धारण में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई के लिए पूर्ण समानता का हकदार है।

आलेख 11

1. दंडात्मक अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष मानने का अधिकार है जब तक कि वह एक सार्वजनिक मुकदमे में कानून के अनुसार दोषी साबित न हो जाए, जिसमें उसके पास अपने बचाव के लिए आवश्यक सभी गारंटी होती है।
2. किसी को भी, उस किसी भी कार्य या चूक के कारण किसी भी दंडात्मक अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जो उस समय राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दंडनीय अपराध नहीं था, जब वह किया गया था। न ही उस दंड से अधिक भारी जुर्माना लगाया जाएगा जो उस समय लागू किया गया था जब दंडात्मक अपराध किया गया था।

आलेख 12

किसी को भी उसकी निजता, परिवार, घर या पत्र-व्यवहार में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर आघात किया जाएगा। इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ हर किसी को कानून के संरक्षण का अधिकार है।

आलेख 13

1. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर आवाजाही और निवास की स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश सहित किसी भी विदेश को छोड़कर अपने देश लौटने का अधिकार है।

आलेख 14

1. हर किसी को अपना उत्पीड़न महसूस होने पर दूसरे देशों में शरण लेने और वहाँ आनंद लेने का अधिकार है।
2. गैर-राजनीतिक अपराधों से या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत कृत्यों से वास्तव में उत्पन्न होने वाले मुकदमों के मामले में इस अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

आलेख 15

1. सभी को राष्ट्रीयता का अधिकार है।
2. किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसकी राष्ट्रीयता को बदलने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

आलेख 16

1. वयस्क आयु के पुरुषों और महिलाओं को जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की बाध्यता की सीमा से ऊपर उठकर शादी करने और परिवार बनाने का अधिकार है।
2. विवाह केवल इच्छुक जीवनसाथी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही किया जाएगा।
3. परिवार समाज की एक प्राकृतिक और मौलिक समूह इकाई है और जिसे समाज और राज्य द्वारा सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

आलेख 17

1. प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का भी अधिकार है।
2. किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

आलेख 18

प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार में अपने धर्म या विश्वास को बदलने की स्वतंत्रता, और अकेले या दूसरों के साथ समुदाय में और सार्वजनिक या निजी रूप से, अपने धर्म या विश्वास को शिक्षण, अभ्यास, पूजा और पालन में प्रकट करने की स्वतंत्रता शामिल है।

आलेख 19

सभी को अपनी राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के राय रखने और किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किए बिना जानकारी और विचार प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता भी शामिल है।

आलेख 20

1. सभी को शांतिपूर्ण सभा करने और एकत्र होने की स्वतंत्रता का अधिकार है।
2. किसी को भी संगठन, संस्था आदि से जुड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

आलेख 21

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।
2. अपने देश में सभी को सार्वजनिक सेवा में समान पहुँच का अधिकार है।
3. लोगों की इच्छा सरकार के अधिकार का आधार होगी। यह समय-समय पर और वास्तविक चुनावों में व्यक्त किया जाएगा, जो सार्वभौमिक और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त वोट या समकक्ष मुक्त मतदान प्रक्रियाओं द्वारा होंगे।

आलेख 22

प्रत्येक व्यक्ति, समाज के सदस्य के रूप में, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार रखता है और राष्ट्रीय प्रयास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से और प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुसार, अपने लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार उसकी गरिमा और उसके व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए अनिवार्य हैं।

आलेख 23

1. प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का, रोज़गार का स्वतंत्र चुनाव करने का, काम की उचित और अनुकूल परिस्थितियों का, और बेरोज़गारी से बचाव का अधिकार है।
2. बिना किसी भेदभाव के सभी को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार है।
3. हर कोई जो काम करता है उसे उचित और अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है, जो अपने और अपने परिवार के लिए मानवीय गरिमा के योग्य अस्तित्व सुनिश्चित करता है, और यदि आवश्यक हो, तो सामाजिक सुरक्षा के अन्य माध्यमों से पूरक है।

4. प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार है।

आलेख 24

प्रत्येक व्यक्ति को आराम और अवकाश का अधिकार है, जिसमें काम के घंटों की उचित सीमा और वेतन के साथ आवधिक अवकाश शामिल हैं।

आलेख 25

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जीवनपर्यन्त पर्याप्त सुरक्षा का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास और चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएँ शामिल हैं, और बेरोजगारी की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। बीमारी, अपंगता, विधवापन, बुढ़ापा या आजीविका के अन्य अभाव ऐसी परिस्थितियों में जो उसके नियंत्रण से बाहर हो।
2. सभी बच्चे, चाहे वे विवाह के बाद पैदा हुए हों या विदेश में, सभी को समान सामाजिक सुरक्षा का आनंद लेने और मातृत्व और बचपन में विशेष देखभाल और सहायता के हकदार हैं।

आलेख 26

1. शिक्षा का अधिकार सभी को है। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, कम से कम प्रारंभिक और मौलिक चरणों में। प्रारंभिक शिक्षा आवश्यक होगी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आम तौर पर उपलब्ध कराई जाए, और उच्च शिक्षा योग्यता के आधार पर सभी के लिए समान रूप से सुलभ होनी चाहिए।
2. शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। यह सभी राष्ट्रों, नस्लीय या धार्मिक समूहों के बीच समझ, सहिष्णुता और मित्रता को बढ़ावा देगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा।
3. माता-पिता को यह चुनने का पूर्ण अधिकार है कि उनके बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए।

आलेख 27

1. प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कलाओं का आनंद लेने और वैज्ञानिक उन्नति और इसके लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक रचना, जिसका वह लेखक है, से उत्पन्न नैतिक और भौतिक हितों की रक्षा का अधिकार है।

आलेख 28

प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूरी तरह महसूस किया जा सके।

आलेख 29

1. प्रत्येक व्यक्ति का उस समुदाय के प्रति कर्तव्य होता है जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है।

2. अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रयोग में, प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसी सीमाओं के अधीन होगा जो कानून द्वारा केवल दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए उचित मान्यता और सम्मान को सुरक्षित करने और नैतिकता की सार्वजनिक व्यवस्था और एक लोकतांत्रिक समाज में सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती है।
3. इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का किसी भी मामले में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

आलेख 30

इस घोषणा में कुछ भी किसी भी राज्य, समूह, या व्यक्ति को किसी भी गतिविधि में शामिल होने या यहाँ दिए गए किसी भी अधिकार और स्वतंत्रता के विनाश के उद्देश्य से किसी भी कार्य को करने के अधिकार के रूप में व्याख्या नहीं की गई है।⁵

जैसा कि हमने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ा, उसमें हमने जो दावा किया उसकी सादगी पर आश्चर्य कर सकते हैं, उसका मज़ाक उड़ा सकते हैं। आज लगभग हर देश - विकासशील और विकसित, स्वतंत्र या अधीन, लोकतांत्रिक या निरंकुश - खुद गवाह है मानवाधिकारों के उल्लंघन करने का।

खुद को वास्तविक दुनिया में लाने के लिए आइए हम एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा चीन और भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर दी गई दो रिपोर्टों को देखें (ताकि हम न केवल उंगली उठाएँ बल्कि आत्म-चिंतन भी कर सकें)। दोनों दस्तावेज़ "डाइजेस्ट" के लिए थोड़े लंबे हैं, इसलिए हम यहाँ केवल कुछ अंश दे रहे हैं, और पाठक को पूरा दस्तावेज़ पढ़ने के लिए वेबलिंग पर क्लिक करने देते हैं।

कुछ अंश - चीन में मानवाधिकारों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2020⁶

वर्ष 2020 मानवाधिकार रक्षकों और असंतुष्ट माने जाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई के साथ-साथ जातीय अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित दमन द्वारा चिह्नित किया गया वर्ष रहा। वर्ष की शुरुआत में वुहान में COVID-19 का प्रकोप शुरू हुआ, जिसने चीन में 4,600 से अधिक लोगों की जान ले ली। अधिकारियों द्वारा वायरस के बारे में चेतावनी देने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों को फटकार लगाने के बाद लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में, चीन की कड़ी आलोचना की गई और झिंजियांग तक तत्काल, सार्थक और निरंकुश पहुँच की अनुमति देने का आग्रह किया गया।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध बेरोकटोक जारी रहे। विदेशी पत्रकारों को नजरबंदी और निष्कासन का सामना करना पड़ा, साथ ही वीजा नवीनीकरण में व्यवस्थित देरी और इन्कार का सामना करना पड़ा। चीन के बाहर काम करने वाली चीनी और अन्य तकनीकी फर्मों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने सेंसरशिप मानकों का विस्तार करते हुए, सरकार को राजनीतिक रूप से संवेदनशील सामग्री के रूप में समझा। चीन ने अपने पहले नागरिक संहिता को अधिनियमित किया, जिसे समान-लिंग विवाह

5 <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

6 <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/>

के वैधीकरण के लिए जनता द्वारा हजारों प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुईं। हाँगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी।

मानवाधिकार रक्षक

संवैधानिक प्रावधानों और अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और दायित्वों के बावजूद, चीन ने अपने मानव अधिकार रक्षकों (HRD) और कार्यकर्ताओं के अपने निरंतर उत्पीड़न को जारी रखा। पूरे वर्ष के दौरान, उन्हें व्यवस्थित रूप से उत्पीड़न, डराने-धमकाने, जबरन गायब करने, और मनमाने ढंग से हिरासत के साथ-साथ कारावास की लंबी अवधि के अधीन किया गया। एक स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रभावी निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी के अभाव में इस तरह के बार-बार होने वाले उल्लंघनों को और बढ़ा दिया गया है। कई मानवाधिकार वकीलों को आंदोलन की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, साथ ही प्रतिवादियों से मिलने और उनका प्रतिनिधित्व करने और केस सामग्री तक पहुँच बनाने के लिए मानव संसाधन विकास और कार्यकर्ताओं को लक्षित किया गया और उन पर व्यापक रूप से परिभाषित और अस्पष्ट शब्दों वाले अपराधों जैसे "राज्य की शक्ति को नष्ट करना", "राज्य की सत्ता को तोड़ना", "राज्य की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना" और "झगड़े करना" और दंगे भड़काना" आदि का आरोप लगाया गया।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों को धारा "709 की कार्रवाई" के रूप में लक्षित अभूतपूर्व कार्रवाई के पाँच साल बाद, कई वकील जेल में या सख्त निगरानी में रहे। 17 जून को, मानवाधिकार वकील (Yu Wensheng) पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया गया और 18 महीने के लिए सम्पर्क-वर्जित होने के बाद कथित तौर पर "राज्य सत्ता के तोड़फोड़ को उकसाने" के लिए चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई। उनके वकील के अनुसार हू (Yu) को हिरासत में प्रताड़ित किया गया जिससे उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया।

स्वायत्त क्षेत्र : झिंजियांग, तिब्बत और भीतरी मंगोलिया

झिंजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र (शिनजियांग) और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (तिब्बत) में "अलगाववाद विरोधी", "अतिवाद विरोधी" और "आतंकवाद विरोधी" के ढोंग के तहत जातीय अल्पसंख्यकों का गंभीर और व्यापक दमन बेरोकटोक जारी रहा। विशेष रूप से पत्रकारों, शिक्षाविदों और मानवाधिकार संगठनों के लिए तिब्बत तक पहुँच और वहाँ से अत्यधिक प्रतिबंधित रहा, जिससे इस क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति की जाँच और दस्तावेजीकरण करना बेहद मुश्किल हो गया। झिंजियांग में, 2017 के बाद से अनुमानित एक मिलियन या अधिक उइगर, कज़ाख, और अन्य मुख्य रूप से मुस्लिम लोगों को बिना किसी मुकदमे के मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया और "परिवर्तन-से-शिक्षा" केंद्रों में राजनीतिक स्वदेशीकरण और जबरन सांस्कृतिक आत्मसात किया गया।

मंगोलिया के अंदर, एक नई "द्विभाषी शिक्षा" नीति पर क्षेत्र-व्यापी विरोध प्रदर्शन हुए, जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा के नौ वर्षों के दौरान मंगोलियाई से मंदारिन चीनी तक कई कक्षाओं के शिक्षण माध्यम को धीरे-धीरे बदल देगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, छात्रों, माता-पिता, शिक्षकों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को केवल "झगड़े करने और परेशानी पैदा करने" के लिए गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था या इंटरनेट पर विरोध के बारे में

जानकारी साझा की थी। मानवाधिकार वकील (Hu Baolong) को कथित तौर पर "विदेशों में राज्य के रहस्यों को लीक करने" के आरोप में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था।

स्वास्थ्य का अधिकार

वुहान में COVID-19 के प्रकोप के शुरुआती हफ्तों के दौरान सरकारी सेंसरशिप ने महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रवाह को बाधित किया। महामारी के प्रारंभिक चरण में, पेशेवर और नागरिक पत्रकारों, साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रकोप पर रिपोर्ट करने से रोका गया था... 21 फरवरी तक, उन व्यक्तियों के खिलाफ पहले से ही 5,511 से अधिक आपराधिक जाँच के मामले थे, जिन्होंने इसके संबंध में जानकारी प्रकाशित की थी। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, COVID-19 महामारी के प्रकोप की "झूठी और हानिकारक जानकारी गढ़ने और जानबूझकर प्रसारित करने" के लिए ----

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

इस समय पर इंटरनेट सेंसरशिप जारी रही, जो आंशिक रूप से COVID-19 और अत्यधिक लॉकडाउन उपायों के बारे में जानकारी को दबाने के प्रयासों से प्रेरित थी। चीनी अधिकारियों द्वारा महामारी के केंद्र वुहान में "झूठी टिप्पणी करने" और "सामाजिक व्यवस्था को गंभीर रूप से परेशान करने" के लिए चिकित्सा पेशेवरों और कार्यकर्ताओं को अत्यधिक प्रताड़ित किया गया था। डॉक्टर (Li Wenliang) उन आठ व्यक्तियों में से एक, जिन्होंने प्रकोप की घोषणा से पहले अलार्म बजाने की कोशिश की थी, को स्थानीय पुलिस ने चार दिन बाद काफी फटकार लगाई थी, जब उन्होंने एक चैट समूह में एक चेतावनी संदेश भेजा था जिसमें साथी डॉक्टरों को संक्रमण से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने के लिए कहा गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप को समाप्त करने की मांग के साथ, COVID-19 से उनकी मृत्यु होने ने इंटरनेट पर राष्ट्रव्यापी आक्रोश और शोक को जन्म दिया। अधिकारियों ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर सैकड़ों कीवर्ड कॉम्बिनेशन को ब्लॉक कर दिया। असंतोष के ऑनलाइन पोस्ट, प्रकोप से संबंधित संवेदनशील हैशटैग, और मुक्त भाषण की मांगों को जल्दी से हटा दिया गया। परन्तु लीक हुए नोटिसों से संकेत मिलता है, कि अधिकारियों ने "अफवाह फैलाने" के आरोपी लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट हटाने का आदेश दिया था...

अप्रैल में, अधिकारियों ने COVID-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के बारे में अकादमिक पत्रों पर नए कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसके अनुमोदन के लिए उन्हें राज्य परिषद द्वारा नियुक्त एक टास्क फोर्स को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। 13 जुलाई को कानून के प्रोफेसर (Xu Zhangrun), जिन्होंने COVID-19 महामारी के प्रकोप पर सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना प्रकाशित की, इसके लिए उन्हें छह दिनों की न्यायायिक हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया। कथित तौर पर जू (Xu) को उनकी रिहाई के एक दिन बाद सिंधुआ विश्वविद्यालय से नौकरी से निकाल दिया गया था। 19 अगस्त को पेकिंग विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन वेबिनार और विदेशी संस्थाओं और साथ ही हाँगकांग और मकाऊ में आयोजित सम्मेलनों में भाग लेने के लिए नियमों के एक नए सेट की घोषणा की। नोटिस में मांग की गई है कि प्रतिभागी किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने से 15 दिन पहले आवेदन करें, और उसके लिए अनुमति प्राप्त करें।

वर्ष के दौरान चीन की सेंसरशिप और निगरानी उसकी सीमाओं से आगे बढ़ी। तब 12 जून को टेलीकांफ्रेंसिंग कंपनी जूम ने खुलासा किया कि उसने चीनी सरकार के अनुरोध पर चीन के बाहर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खातों को निलंबित कर दिया था और सुझाव दिया था कि यह आगे की उन बैठकों को रोक देगा जिसे सरकार "अवैध" मानती है ...

धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता

1 फरवरी से प्रभावी नियम, यह निर्धारित करते हैं कि धार्मिक समूहों को "चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व का पालन करना चाहिए ... धर्म के पापीकरण की दिशा में बने रहना चाहिए, और मूल समाजवादी मूल्यों का अभ्यास करना चाहिए"। सरकार ने धार्मिक शिक्षाओं और प्रथाओं को राज्य की विचारधारा के अनुरूप लाने और राज्य-अनुमोदित और अपंजीकृत दोनों धार्मिक समूहों पर नियंत्रण को व्यापक रूप से मजबूत करने की मांग की। रिपोर्टों ने हजारों सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विनाश का दस्तावेजीकरण तैयार किया, विशेष रूप से चीन के उत्तर-पश्चिम में। शिनजियांग और तिब्बत राज्य में धर्म का दमन गंभीर रहा। लोगों को सामान्य धार्मिक प्रथाओं के लिए मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया था, जिन्हें अधिकारियों ने "विस्तारीकरण नियम" के तहत "चरमपंथ के संकेत" के रूप में समझा।

समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स (LGBTI) लोग

13 अगस्त को, चीन के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले (LGBTI) उत्सव, शंघाई प्राइड ने (LGBTI) समुदाय के लिए कम होते चलन के बीच भविष्य की सभी गतिविधियों को रद्द करने की घोषणा की। भेदभाव और होमोफोबिया (समलैंगिकों के प्रति हीन भावना) के खिलाफ बोलने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। माइक्रोब्लॉग और पत्रिकाओं सहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने एलजीबीटीआई से संबंधित सामग्री और हैशटैग को अवरुद्ध कर दिया और हटा दिया। विभिन्न चुनौतियों और बढ़ते दबाव के बावजूद, एलजीबीटीआई समुदायों के सदस्य अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। एक विश्वविद्यालय के छात्र ने कथित तौर पर सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यपुस्तक में समलैंगिक और समलैंगिक लोगों के संदर्भ में "सामान्य मनोवैज्ञानिक विकार" से पीड़ित होने के बारे में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की। अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया।

हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र

चीन के शीर्ष विधायिका ने हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) में राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के व्यापक शब्दों वाले कानून को अपनाया। स्थानीय सरकार ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी और मीडिया और शिक्षा क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के बहाने राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल किया। COVID-19 महामारी के संदर्भ में शारीरिक दूरी के नियमों को मनमाने ढंग से लागू करके शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकार को और कम कर दिया गया।

विधानसभा और संघ की स्वतंत्रता

शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का दमन 2019 में विरोध प्रदर्शनों के बाद भी जारी रहा। नए साल के दिन विरोध प्रदर्शन में सिर्फ तीन घंटे में, पुलिस ने एक स्वीकृत प्रदर्शन को "गैरकानूनी" घोषित कर दिया,

और बड़े पैमाने पर आयोजकों और दसियों हजार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए 30 मिनट का समय दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आँसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें शुरू कीं और तीन मानवाधिकार निगरानीकर्ताओं सहित 287 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 18 अप्रैल को अधिकारियों ने लोक व्यवस्था अध्यादेश का उल्लंघन करने के लिए 15 प्रमुख लोकतंत्र समर्थक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। यह कानून अक्सर बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोधों को प्रतिबंधित करने और समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन पर "अनाधिकृत सभा" आयोजित करने और सभा में शामिल होने का आरोप लगाया गया था जो सभा उनकी गिरफ्तारी से छह महीने पहले हुई थी।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के बहाने राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल किया गया। वस्तुतः किसी भी चीज को बिना किसी सार्थक परामर्श के 30 जून को अपनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अत्यंत अस्पष्ट प्रावधानों के तहत "राष्ट्रीय सुरक्षा" के लिए खतरा माना जा सकता है और अगले दिन प्रभावी हो सकता है। शांतिपूर्ण गतिविधियों पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों को नया आधार देते हुए, कानून स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर एक ठंडा प्रभाव पैदा किया। और 11 वर्षों में अधिकारियों ने 34 व्यक्तियों को राजनीतिक नारे प्रदर्शित करने, हाँगकांग की स्वतंत्रता के लिए विदेशी संगठनों की स्थापना करने, या विभिन्न राजनीतिक समूहों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने कानून के अलौकिक प्रावधान को भी लागू किया और हाँगकांग के बाहर रह रहे आठ कार्यकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया ...

मानवाधिकारों का चीनी आधिकारिक संस्करण

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक भाषण में, चीन के विदेश मंत्री ने इस अवधारणा को **चीन का पसंदीदा रिपन** नाम दिया⁷

Shannon Tiezzi द्वारा, 21 फरवरी, 2021

22 फरवरी, 2021 को चीनी विदेश मंत्री Wang Yi ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में भाषण दिया। यह पहली बार था जब एक चीनी सरकारी अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार निकाय को संबोधित किया था - और भाषण में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बेहतर तरीके से मानव अधिकारों की अवधारणा को रीमेक करने के बीजिंग के प्रयास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग थे।

1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद से सीसीपी (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया है। पीआरसी (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) के शुरुआती दिनों में व्यापारियों और बुद्धिजीवियों को निशाना बनाने से लेकर 1959 में तिब्बत में कार्रवाई से लेकर सांस्कृतिक क्रांति के रक्तपात तक। राजनीतिक उत्पीड़न सीसीपी शासन की एक बानगी रही है - 1989 के तियानमेन स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों पर सैन्य कार्रवाई के साथ

⁷ <https://thedi diplomat.com/2021/02/can-china-change-the-definition-of-human-rights/>

शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में। जो आज बीजिंग के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा धब्बा है, जोकि चीन के शिनजियांग क्षेत्र में तुर्क मुस्लिम समूहों, विशेष रूप से मूल उइगरों के खिलाफ चल रहा अभियान है। उस विशेष आक्रोश में, जिसमें सामूहिक हिरासत, जबरन श्रम और निरंतर निगरानी शामिल है, ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर चीन पर एकमुश्त नरसंहार का आरोप लगाया।

22 फरवरी को Wang Yi के भाषण ने झिंजियांग और हाँगकांग के प्रति चीन की नीतियों का बचाव करने के लिए एक ठोस हिस्सा समर्पित किया, जहाँ पिछले साल एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हुआ था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके। लेकिन अधिक व्यापक रूप से, उनकी टिप्पणी ने "मानवाधिकारों" की परिभाषा को सीसीपी की ताकत के अनुकूल एक और परिभाषा में स्थानांतरित करने की मांग की।

Wang Yi का "जन-केंद्रित" मानवाधिकार का प्रस्ताव "लोगों के लाभ, खुशी और सुरक्षा की भावना" को "मानव अधिकारों की मौलिक खोज" के रूप में प्रस्तुत करता है। इस सूत्रीकरण में आर्थिक समृद्धि सूची में सबसे ऊपर है, "खुशी" जो कि अस्पष्ट अवधारणा है, नस्लीय और लैंगिक समानता या धर्म की स्वतंत्रता जैसे अधिक ठोस मार्करों की जगह लेती है, जिसमें सुरक्षा को मानवाधिकारों की प्राथमिकता तक बढ़ा दिया जाता है।

Wang के मानवाधिकारों की पूरी गणना में "शांति, विकास, समानता, न्याय, लोकतंत्र और स्वतंत्रता" की अवधारणाएँ शामिल हैं। यहाँ की व्यवस्था - शीर्ष पर शांति और आर्थिक विकास, लोकतंत्र और सबसे नीचे स्वतंत्रता - विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस संदर्भ में, Wang ने 2020 में अत्यधिक गरीबी को खत्म करने के चीन के दावे को "हमारी मानवाधिकार उपलब्धि में एक मील का पत्थर" बताया।

जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Wang Wenbin ने उसी दिन Wang Yi के भाषण के रूप में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "चीन एक जन-केंद्रित दृष्टि का अनुसरण करता है, निर्वाह और विकास के अधिकारों को प्राथमिक, बुनियादी मानवाधिकार मानता है, और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के साथ-साथ नागरिक राजनीतिक अधिकारों का व्यापक और समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करता है। "राजनीतिक अधिकारों" पर वरीयता लेने के रूप में "आर्थिक" अधिकारों पर चीन का जोर यही कारण है, कि बीजिंग अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड की रक्षा के लिए लगातार आर्थिक विकास के आँकड़े लाता है। जब Wang Wenbin ने तर्क दिया कि "पिछले 60 से अधिक वर्षों में, झिंजियांग की कुल अर्थव्यवस्था 200 गुना से अधिक बढ़ी है, यानि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लगभग 40 गुना है, और लोगों की यह जीवन प्रत्याशा 30 से 72 वर्षों में बढ़ी है," इसका तात्पर्य यह है कि यह आर्थिक विकास बीजिंग को वहाँ पहुँचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी साधन को सही ठहराता है।

जहाँ तक "सुरक्षा" के मानव अधिकार का सवाल है, बीजिंग का एक और सामान्य विरोध है - जो सोमवार को Wang Yi द्वारा दोहराया गया - कि शिनजियांग में आतंकवादी गतिविधि के लिए इसपर कार्रवाई एक उचित प्रतिक्रिया है। चीनी अधिकारियों ने अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 2017 के बाद से शिनजियांग में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, और सुरक्षा दृष्टि से मानव अधिकार पर कार्रवाई उचित है, चाहे मानव अधिकारों के पश्चिमी अर्थों में इसकी जो भी कीमत हो - उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति, धर्म और मिलने-जुलने की आज़ादी।

आर्थिक और भौतिक सुरक्षा को शामिल करने के लिए मानव अधिकारों की परिभाषा को बढ़ावा देकर चीन अनिवार्य रूप से लक्ष्य पदों को स्थानांतरित करने की उम्मीद कर रहा है ताकि वह मानवाधिकार संरक्षण के नैतिक उच्च आधार के लिए उदार लोकतंत्रों (विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका) के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सके। जैसा कि Wang Yi ने अपने भाषण में कहा था, "मानव अधिकार कुछ देशों द्वारा अपनाया एकाधिकार नहीं हैं, फिर भी उन्हें अन्य देशों पर दबाव बनाने और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। Wang Wenbin स्तब्ध थे - क्योंकि चीन चाहता है कि UNHRC "मानव अधिकारों के बहाने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों और दोहरे मानकों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करे।"

जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में मानवाधिकारों की वकालत करने वाले मानवाधिकारों की बदलती परिभाषा से नाराज हो सकते हैं, बीजिंग का सूत्रीकरण बड़ी संख्या में देशों के लिए आकर्षक है - विशेष रूप से अन्य सत्तावादी-इच्छुक सरकारों के लिए। आखिरकार, Wang Wenbin के अनुसार, मानवाधिकार परिषद के लिए चीन का बार-बार चुनाव, "चीन के मानवाधिकारों के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता की ही गवाही देता है।"

अब सवाल यह उठता है, कि आने वाले वर्षों में मानवाधिकार परिषद कैसे काम करेगी। क्या मानवाधिकार परिषद चीन के मानवाधिकारों की नई परिभाषा को तेजी से अपनाएगी, जो विकास-केंद्रित जोर के पक्ष में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को चुपचाप दरकिनार कर देती है? जैसा कि म्यांमार में तख्तापलट - और अब तक वैश्विक कार्रवाई की कमी साबित करती है, इस प्रश्न में गंभीर पेंच हैं जो चीन से बहुत आगे तक फैले हुए हैं।

कुछ अंश: भारत में मानवाधिकारों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2020⁸

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी चुनिंदा रूप से दी गई थी, और शांतिपूर्ण विरोधों पर गैरकानूनी प्रतिबंधों और आलोचकों को चुप कराने के माध्यम से असंतोष का दमन किया गया था। छात्रों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और कलाकारों सहित मानवाधिकार रक्षकों को मनमाने ढंग से अक्सर बिना किसी आरोप या मुकदमे के गिरफ्तार किया गया। COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए, जेल की भीड़भाड़ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, अधिकारियों ने सरकार की आलोचना करने वाले कई लोगों को जेल में डालना जारी रखा। वे अधिकारी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर हिंसा के अपराधियों को पर्याप्त जाँच या दंड देने में विफल रहे, और बलात्कार और जाति आधारित अपराधों की रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ प्रतिशोध किया। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ चौकस भीड़ और पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई हत्याओं और हमलों के लिए व्यापक दण्ड से मुक्ति और जवाबदेही की कमी थी। महामारी के जवाब में आंदोलन की स्वतंत्रता पर तेजी से और अत्यधिक प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे हजारों प्रवासी श्रमिक पर्याप्त भोजन और सुरक्षा के बिना फँसे हुए थे। महामारी पर अंकुश लगाने के लिए कुछ प्रतिबंधों ने निजता के अधिकार को भी खतरे में डाल दिया।

⁸ <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/india/report-india/>

पृष्ठभूमि

दिसंबर 2019 में, सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) पारित किया, जिससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अनियमित प्रवासियों को मुसलमानों को छोड़कर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में मदद मिली। सीएए की भेदभावपूर्ण प्रकृति ने देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जो मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और नजरबंदी और विरोध करने वालों के व्यापक प्रदर्शन के साथ मिले। COVID-19 पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की रणनीति में बहुत ही कम समय में दंडात्मक लॉकडाउन, राहत राशि के वितरण में पारदर्शिता की कमी, गोपनीयता के लिए खतरा और धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रदर्शन शामिल है।

मनमानी गिरफ्तारी और विरोध

सात मानवाधिकार कार्यकर्ताओं - फादर स्टेन स्वामी, ज्योति राघोबा जगताप, सागर तात्याराम गोरखा, रमेश मुरलीधर गायचोर, हनी बाबू, गौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बडे को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए), भारत की मुख्य आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। 2018 में पुणे शहर के पास भीमा कोरेगाँव समारोह के दौरान हिंसा में उनकी कथित संलिप्तता के कारण। गिरफ्तार किए गए लोगों ने आदिवासी (स्वदेशी) समुदायों सहित उपेक्षित समूहों के साथ काम किया, और सरकारी नीतियों की आलोचना की थी। सरकार ने उन पर "देश के खिलाफ युद्ध छेड़कर" दंड संहिता का उल्लंघन करने और प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया ...

सीएए के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कम से कम नौ छात्रों को आतंकवाद विरोधी और राजद्रोह कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। कई अन्य सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को पुलिस की तीव्र धमकी और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। इस बीच, अधिकारियों ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सहित आतंकवाद विरोधी कानूनों का विरोध करने वालों के खिलाफ सीएए के समर्थकों द्वारा हिंसा और अभद्र भाषा को नजरअंदाज कर दिया। सफूरा जरगर, एक शोध छात्रा, जो उस समय तीन महीने की गर्भवती थी, और उमर खालिद, एक पूर्व छात्र संघ नेता, गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थे। बाद में सफूरा जरगर को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

26 जून को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भारत से सीएए के विरोध में गिरफ्तार किए गए मानवाधिकार रक्षकों को तुरंत रिहा करने का आह्वान किया। हालाँकि, साल के अंत तक अधिकांश लोगों को हिरासत में ही रहना पड़ा था...

अभिव्यक्ति और विधान सभा की स्वतंत्रता

COVID-19 महामारी के जवाब में अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता पर नए प्रतिबंध लगाए गए थे। 24 मार्च को, प्रधान मंत्री मोदी ने एक राष्ट्रव्यापी तालाबंदी लागू की, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अनिवार्य 'स्टे-एट-होम' व क्वारंटाइन (संगरोध व घर में कैद) शामिल था, एक कठोर कानून जो सरकार को आपदा स्थितियों में व्यापक अधिकार देता है। तालाबंदी के उल्लंघन के परिणामस्वरूप लोगों को हिरासत में लिया गया। महामारी से पहले भी, सभा की स्वतंत्रता प्रतिबंधित थी, जिसमें

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की लागत की वसूली के साथ नागरिकों पर बोझ डालना शामिल था।

सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के एक साल बाद भी नागरिक स्वतंत्रता और संचार सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहा। 2019 में प्रशासनिक रूप से हिरासत में लिए गए फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे राजनीतिक नेताओं को 2020 में रिहा कर दिया गया। हालाँकि, केंद्र सरकार ने जवाबदेही की मांग करने वालों को चुप कराना जारी रखा और कठोर मीडिया ब्लैकआउट लगाया...

COVID-19 महामारी के प्रकोप के बाद लगाए गए देशव्यापी तालाबंदी के दौरान, 50 से अधिक पत्रकारों को "गलत सूचना" या "फर्जी समाचार" फैलाने के लिए आपातकालीन कानूनों के तहत आरोपित या गिरफ्तार किया गया था। 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पत्रकार प्रशांत कनौजिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रधान मंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में "आपत्तिजनक टिप्पणी" करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने द वायर, एक दैनिक समाचार वेबसाइट, और इसके संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें बताया गया था कि योगी आदित्यनाथ ने देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद एक सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया था।

28 सितंबर को सरकार ने विदेशी अंशदान अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन किया, जिससे बड़े गैर सरकारी संगठनों को विदेशी दानदाताओं से जमीनी स्तर पर प्राप्त होने वाले धन पर रोक लगा दी गई। नए संशोधनों में सभी एफसीआरए-पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों को अपने प्रशासनिक खर्चों को दान के 20% (पहले के 50% से) तक सीमित करने की जरूरत है। इस संशोधन से गैर सरकारी संगठनों को अपने कर्मचारियों को कम करने के लिए मजबूर करने की संभावना थी, और यह परोक्ष रूप से मानवाधिकार कम करने का कार्य था।

30 सितंबर को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उसके सभी बैंक खातों को सील करने के बाद अपना परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संगठन को अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टी करने और अपने सभी अभियान और शोध कार्यों को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यह सब तब हुआ जब एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने दिल्ली दंगों के दौरान और जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में दिल्ली पुलिस और सरकार द्वारा किए गए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए ब्रीफिंग प्रकाशित की थी।

अनुचित परीक्षण

अदालतें, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, सही समय पर सही ढंग से COVID-19 संकट पर सरकार की प्रतिक्रिया की निगरानी करने में विफल रही। 13 मार्च को, राष्ट्रीय तालाबंदी लागू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की, कि अदालतें - सार्वजनिक स्वास्थ्य कारणों से - कम क्षमता पर काम करेंगी। 23 मार्च और 4 जुलाई के बीच सुप्रीम कोर्ट केवल "अत्यधिक आवश्यकता" के मामलों पर सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ और शारीरिक सुनवाई के बजाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई की सुविधाओं पर भरोसा किया...

गैरकानूनी हमले और हत्याएँ

फरवरी में राजधानी नई दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दंगों में 53 लोग - ज्यादातर मुस्लिम लोग - मारे गए और 500 से अधिक घायल हुए। 8 फरवरी को दिल्ली में हुए विधान सभा चुनावों में, कई राजनीतिक नेताओं ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए। 27 जनवरी को दिल्ली उपरिकेंद्र शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना देने वाले प्रदर्शनकारियों का जिक्र करते हुए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भीड़ को "देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को " के नारे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। 28 जनवरी को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद परवेश वर्मा ने दावा किया कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी आम नागरिकों के घरों में घुसंगे और " उनकी बहनों और बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे और उन्हें मार देंगे"। उसी दिन एक अन्य भाषण में, उन्होंने दिल्ली में चुनावों में भाजपा की चुनावी जीत होने पर "[मस्जिदों] में एक को भी खड़े नहीं रहने देने" का वादा किया था।

इन भाषणों के बाद सीएए का विरोध करने वालों के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा हुई। दिल्ली चुनाव के बाद भी राजनीतिक नेताओं के अभद्र भाषा के भाषण जारी रहे, जिसके बाद दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में व्यापक हिंसा हुई। 23 फरवरी को भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर लोगों से दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले के जाफराबाद में महिलाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के खिलाफ रैली करने का आह्वान किया, जिसमें लोगों से "एक और शाहीन बाग बनाने से रोकने" का आग्रह किया गया। रैली में उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों ने शाहीन बाग साइट खाली नहीं की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनके भाषण के तुरंत बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी।

शक्ति का अत्यधिक उपयोग

पुलिस ने गैरकानूनी बल का इस्तेमाल किया, और कई अन्य मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, लोगों को डराने धमकाने के लिए कानूनों का दुरुपयोग किया और केंद्र सरकार की ओर से असंतोष को शांत किया। दिल्ली में फरवरी की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के सदस्यों ने दंगाइयों के साथ मिलकर पथराव किया, और हिरासत में लोगों को प्रताड़ित किया | शांतिपूर्ण विरोध स्थलों को नष्ट किया, दंगाइयों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नष्ट कर दिया। इन कृत्यों में अभी तक कोई स्वतंत्र जाँच शुरू नहीं की गई थी।

19 जून को कम आय वाले श्रमिक P. Jayaraj और उनके बेटे J. Bennicks को तमिलनाडु में थूथुकुडी पुलिस ने तालाबंदी के दौरान अपनी छोटी सी दुकान खुली रखने के आरोप में पूछताछ के लिए उठाया था। पुलिस हिरासत में कथित तौर पर उन दोनों लोगों को पीट-पीटकर मार डाला गया।

दण्ड से मुक्ति / माफी

पुलिस ने गैरकानूनी हत्याओं को अंजाम देना जारी रखा - कुछ हद तक न्याय के निष्पादन के लिए - दण्ड से मुक्ति के साथ। कश्मीर में जुलाई में एक सेब के बाग में तीन युवा मजदूरों को भारतीय सेना के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से मार दिया गया था। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, जो कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों द्वारा बल के उपयोग को नियंत्रित करता है, सुरक्षा बलों के सदस्यों को कथित मानवाधिकार उल्लंघन के लिए अभियोजन से आभासी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले एक टवीट में दावा किया था, कि उसने 2017 के बाद से 5,178 पुलिस की कार्यवाहियों में 103

"अपराधियों" को मार डाला और 1,859 अन्य को घायल कर दिया - कथित गैर-न्यायिक निष्पादन के लिए राज्य के निर्वाहकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य अभिव्यक्ति।

दलितों, आदिवासी (स्वदेशी) समुदायों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा सहित घृणित अपराध भी दण्ड से मुक्ति के साथ किए गए। सितंबर में, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में प्रमुख जाति के पुरुषों के एक समूह द्वारा एक दलित महिला का कथित रूप से बलात्कार और हत्या कर दी गई थी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके परिवार की सहमति के बिना ही आधी रात के अँधेरे में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद ही आरोपी पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और देशद्रोह के लिए कई प्राथमिकी दर्ज की गई।

स्वास्थ्य और आजीविका का अधिकार

COVID-19 महामारी से निपटने ने सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया। इसके परिणामस्वरूप उन लोगों के लिए असुरक्षित और खराब काम करने की स्थिति भी हुई, जिनके पास पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा नहीं है, जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग।

सरकार ने मुस्लिम तबलीगी जमात अल्पसंख्यक के सदस्यों पर COVID-19 फैलाने का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से मुसलमानों को वंचित कर दिया गया। अप्रैल 2020 में मुस्लिम गर्भवती महिलाओं और कैंसर रोगियों का ईलाज करने वाले से मना करने वाले अस्पतालों के उदाहरण सामने आए। मार्च में देशव्यापी तालाबंदी के बाद के महीनों में, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के साथ-साथ फर्जी समाचारों और अन्य गलत सूचनाओं की बाढ़ आ गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित मामले में सुनवाई करने में देरी की, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के लिए परिवहन, भोजन, और आश्रय, की मांग की गई थी, जो अचानक तालाबंदी के कारण एक महीने से अधिक समय से फँसे हुए थे। 7 अप्रैल को जब सरकार द्वारा प्रायोजित या सार्वजनिक परिवहन की अनुपस्थिति में कई प्रवासी श्रमिक अपने दूर के घरों की ओर जा रहे थे, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश - एस ए बोबडे ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, कि सुप्रीम कोर्ट अगले 10-15 दिनों के लिए "सरकार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।" तालाबंदी के दौरान अन्य जिलों या राज्यों में लंबी दूरी तय करने के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 200 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। मई में जनता के भारी दबाव के बाद, सरकार ने फँसे हुए प्रवासी कामगारों के लिए विशेष ट्रेनें चलाना शुरू किया। हालाँकि, इन ट्रेनों में भोजन और पानी की कमी से कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें चार साल का बच्चा भी शामिल है, जिसकी भूख से मौत हो गई...

भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की रिपोर्ट⁹

NHRC ने विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए 12 सुझाव जारी किए थे, जो अब प्राप्त हुए हैं। जो कि इस प्रकार से हैं -- 1. महिलाओं के अधिकार, 2. एलजीबीटीक्यूआई के अधिकार, 3. मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार, 4. व्यवसाय व मानवाधिकार और भविष्य की प्रतिक्रियाएँ, 5. कैदियों और पुलिस कर्मियों के मानवाधिकार और भविष्य की प्रतिक्रियाएँ। 6. अनौपचारिक कार्यकर्ता और भविष्य की प्रतिक्रियाएँ। 7. बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार, 8. मानव तस्करी का मुकाबला करना, 9. मानव अधिकारों और भविष्य की प्रतिक्रिया पर COVID-19 महामारी का प्रभाव, 10. भोजन, 11. विकलांगता, 12. बच्चे।

NHRC (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग) इंडिया ने देश भर में तालाबंदी के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में फँसे प्रवासी मजदूरों की चुनौतियों और दुःखों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 2020 में एक स्वतः दायर याचिका संख्या 6 के साथ हस्तक्षेप और निर्देशों के लिए एक आवेदन दायर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने एनएचआरसी के हस्तक्षेप को स्वीकार किया। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठताछ की गई--

1. जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली में छात्रों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दिसंबर 2019 में सीए के विरोध के दौरान, जामिया विश्वविद्यालय में जाँच विभाग की एक टीम ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत पर मौके का दौरा किया। जाँच दल ने घटना में गहन जाँच के बाद कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर पाया, कि इसमें हिंसा, भीड़ का गैरकानूनी जमावड़ा, अराजकता आदि का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अगस्त 2020 में प्रस्तुत की।
2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीए के विरोध के उल्लंघन में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की सूचना दी गई। दिसंबर 2019 में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक दायर याचिका में घटना के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में NHRC को जाँच सौंपी। जाँच टीम ने अप्रैल 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जाँच दल ने पाया कि कोई भी छात्र अवैध हिरासत में नहीं था और स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस की कार्रवाई भी उचित थी। जाँच रिपोर्ट माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की गई जिसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया।
3. फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में व्यापक दंगों की घटना पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था और पुलिस की भूमिका निष्पक्ष थी या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल जाँच का आदेश दिया गया था। और उस क्षेत्र के लोगों के धर्म की परवाह किए बिना स्थिति से निपटने में निष्पक्ष और विवेकपूर्ण जाँच के लिए टीम का गठन किया गया, जाँच प्रभाग द्वारा मौके पर जाँच करने के बाद अप्रैल 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने दंगों (मृत और घायल दोनों) के पीड़ितों के मुआवजे और पुनर्वास की सिफारिश की, दिल्ली पुलिस के आयुक्त को आपराधिक मामलों की शीघ्रता से जाँच करने का निर्देश दिया। दिल्ली के उत्तरपूर्वी हिस्से में फैल रहे अवैध हथियारों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। अन्य सिफारिशों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति की खुफिया जानकारी और पेशेवर संचालन को मजबूत करना शामिल है।

⁹ <https://nhrc.nic.in/document/2020-21-year-end-review>

अंतरमन का गणराज्य- Seamus Heaney की कविता

यह कविता नोबेल पुरस्कार विजेता आयरिश कवि, नाटककार, और अनुवादक Seamus J Heaney, द्वारा (1939-2013), में लिखी गई थी उनका काम अक्सर आयरलैंड के स्थानीय परिवेश से संबंधित है, विशेष रूप से उत्तरी आयरलैंड में, जहाँ उनका जन्म हुआ और युवा वयस्कता तक जीवित रहे। उन्हें 1995 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को चिह्नित करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल आयरलैंड की प्रमुख Mary Lawlor, के विशिष्ट अनुरोध पर कविता लिखी थी। 1985 में जब Mary Lawlor, ने Seamus J Heaney से संपर्क किया और उनसे एक लेख लिखने का अनुरोध किया, तो उन्होंने उन्हें एक डोजियर सौंपा, जो पुरुषों और महिला दोनों की कहानियों से भरा हुआ था, जिन्होंने यातना, कारावास और चुप्पी का सामना किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का सर्वोच्च पुरस्कार - एंबेसडर ऑफ कॉन्शियस इसी काम से प्रेरित है। अपने परिचय में हेनी ने अपनी कविता के बारे में कहा :

"मैंने यह मान लिया था कि अंतरमन का गणराज्य - एक शांत, एकान्त स्थान होगा; जहाँ एक व्यक्ति का आत्म-जागरूकता और आत्म-परीक्षा से बचना मुश्किल होगा; और इसने मुझे Orkney के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जब मैं पहली बार वहाँ पहुँचा तो मुझे सन्नाटा याद आ गया। जब मैं छोटे प्रोपेलर विमान से उतरा और घास के पार चलना शुरू कर दिया, तो एक छोटी सी झोपड़ी में मैंने एक जलमुर्गी के रोने की आवाज सुनी। और जैसे ही वह छवि मेरे पास आई, मैं एक ऐसी कल्पित कथा को आगे बढ़ाने में सक्षम हुआ जोकि अभी तक निरर्थक थी। एक काल्पनिक चीज जो दुनिया की वास्तविकता की तुलना में एक काउंटरवेट के रूप में स्केल पर लटकायी जा सकती है।"

अंतरमन का गणराज्य Republic of Conscience

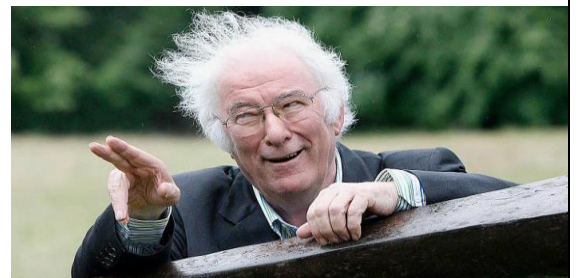
I

अंतरमन गणराज्य इतना शांत था कि
हवाई जहाज के इंजन बंद होते ही
रनवे के ऊपर उड़ रही एक जलमुर्गी का स्वर सुना ।

इमिग्रेशन के एक बूढ़े क्लर्क ने
अपने खादी कोट से एक बटुआ सिला
और मुझे मेरे दादाजी की एक तस्वीर दिखाई।

कस्टम पर खड़ी महिला ने मुझे डिक्लेयर करने को कहा
अपनी पारंपरिक औषधियाँ और कुछ आकर्षक शब्द
जो मूर्खता को ठीक करते और बुरी नजर से बचाते हैं।

खैर तब वहाँ... न कोई कुली। न कोई दुभाषिया। न कोई टैक्सी थी।
अपना बोझ खुद उठाया और बहुत जल्द
विशेषाधिकारों के लक्षण नदारद हो गए।



II

कोहरा वहाँ एक भयानक अपशुन है, पर गाज गिरना
सार्वभौमिक भलाई का मंत्र, और माता-पिता लटकाते हैं
आंधी तूफानों के दौरान झूमते पेड़ों में अपने बच्चे।

नमक उनका कीमती खनिज है, और शंख
जन्म और अंत्येष्टि के दौरान कान में लगाए जाते हैं।
सभी स्याहियों व रंगने वाले पदार्थ का आधार समुद्री जल है।

उनका पवित्र प्रतीक - एक तरह की नाव है।
पाल उसके कान हैं, मस्तूल एक झुकी हुई कलम
पतवार मुँह के आकार की झपझपाती खुली आँख है।

जन नेता अलिखित कानून को बनाए रखने की शपथ लेते हैं
और रोते हैं पद पाने के समभावित दंभ पर
और प्रायश्चित के गीत गाते हैं।

करते हैं वे इस मान्यता की पुष्टि
कि आदि पुरुष के आँसुओं के
नमक से बनी है सारी सृष्टि
वोह आंसू, जो उसके अकेलेपन से उबरे

III

मैं उस मितव्ययी गणराज्य से वापस आया
मेरी दोनो भुजाओं की लंबाई बराबर थी,
कस्टम महिला ने कहा की मुझे

अपने आप को वापिस ले जाने की अनुमति है ।
मेरे चेहरे पर नज़र डॉल बूढ़े क्लर्क ने कहा
कि अब मुझे वहाँ की नागरिकता भी प्रदान की जाती है

इसलिए, जब मैं घर पहुंचूँ तो स्वयं को उनका प्रतिनिधि मानूँ
और उनका संदेश प्रसारित करूँ
उसने कहा, उनके दूतावास हर जगह हैं, स्वतंत्र रूप से संचालित
पर किसी भी राजदूत को कभी भी मुक्त नहीं किया जाएगा।

संपादक द्वारा सुनाई कविता "फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ कॉन्शियस" का लिंक दिया गया है ।

<https://rgfindia.org/wp-content/uploads/2021/05/From-the-Republic-of-Conscience.mpeg>

मुद्दा 3 - हम बेहतर तरीके से इंसानों को प्रकृति से कैसे जोड़ सकते हैं?

और अंत में, दो विषय, 2 और 3 एक हो जाते हैं, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जिसने निम्नलिखित संकल्प को अपनाया। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के प्रति उत्सुक पाठक उस अंत तक जा सकते हैं जहाँ तक कार्रवाई के लिए आइटम हमारे द्वारा बोल्ड में हाइलाइट किए गए हैं]

UN HRC संकल्प 46/7... मानवाधिकार और पर्यावरण¹⁰

मानवाधिकार परिषद 46 वां सत्र 22 फरवरी-23 मार्च 2021

मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, वियना घोषणा और कार्रवाई के कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए, और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रीय मानवाधिकार समूहों को वापस बुलाना

मानवाधिकारों और पर्यावरण पर अपने सभी प्रस्तावों की पुष्टि करते हुए, जिनमें से सबसे हाल ही में 22 मार्च 2018 के संकल्प 37/8, मानवाधिकार और पर्यावरण पर, स्वस्थ वातावरण के माध्यम से बच्चे के अधिकारों को साकार करने पर 7 अक्टूबर 2020 के 45/30 संकल्प और महासभा और मानवाधिकार आयोग के प्रासंगिक संकल्प,

25 सितंबर 2015 के महासभा संकल्प 70/1 की पुष्टि करते हुए, "हमारी दुनिया को सतत विकास के लिए एजेंडा बदलना" 2030 शीर्षक से जिसमें विधानसभा ने सार्वभौमिक और परिवर्तनकारी सतत विकास लक्ष्यों और लक्ष्यों के एक व्यापक, दूरगामी और जन-केंद्रित सेट को अपनाया,

जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन "भविष्य हम चाहते हैं" के परिणाम और इसके दस्तावेज को याद करते हुए, जिसने पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के सिद्धांतों की पुष्टि की,

यह पुष्टि करते हुए कि सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित हैं, *राज्य मानवाधिकार परिषद के सदस्य नहीं है। 1 महासभा संकल्प 66/288, अनुबंध। संयुक्त राष्ट्र A/HRC/46/L.6/Rev.1 महासभा जिला : लिमिटेड 17 मार्च 2021 मूल: अंग्रेजी A/HRC/46/L.6/Rev.1 2 के पहले भाग के परिणाम को याद करते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का पाँचवाँ सत्र, फरवरी 2021 में ऑनलाइन आयोजित किया गया, और फरवरी 2022 में नैरोबी में फिर से शुरू होने वाले पाँचवें सत्र के दूसरे भाग की प्रतीक्षा में...

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों द्वारा 12 दिसंबर 2015 को अपनाए गए पेरिस समझौते को भी याद करते हुए, जिसमें उन्होंने प्रस्तावना में स्वीकार किया था कि उन्हें जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए कार्रवाई करते समय, सम्मान, को बढ़ावा देना चाहिए और अपने सम्बोधन पर विचार करना चाहिए। मानवाधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वदेशी लोगों,

¹⁰ <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/065/30/pdf/G2106530.pdf?OpenElement>

स्थानीय समुदायों, प्रवासियों, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और कमजोर परिस्थितियों में लोगों के अधिकारों और विकास के अधिकार के साथ-साथ लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण के अधिकार के संबंध में दायित्व और अंतर पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देना चाहिए।

मानवाधिकारों के लिए कार्य करने के लिए महासचिव के आह्वान को ध्यान में रखते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, युवाओं को उनके भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों को आकार देने के लिए कार्य करना शामिल है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा, और पर्यावरण की रक्षा करना शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें कार्यकर्ताओं, के लिए विशेष रूप से युवा लोगों, महिलाओं और लड़कियों, में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा पर जोर देने के लिए जो युवाओं को उनके सामने आने वाले भविष्य के लिए तैयार करती है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सभी स्तरों पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन के 25 वें सत्र के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, और अन्य पहलुओं के साथ-साथ, 26 वें सत्र पर मानवाधिकारों के सम्मान और प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, जो ग्लासगो, ग्रेट ब्रिटेन, और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम में 1 से 12 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा।

जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन के 14वें सत्र के परिणामों को भी ध्यान में रखते हुए, और पक्षों को संरक्षण के संदर्भ में मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, कुनमिंग, चीन में आयोजित होने वाले 15वें सत्र में 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता ढाँचे को अपनाने की उम्मीद है।

यह स्वीकार करते हुए कि जैव विविधता का क्षरण और हानि अक्सर भेदभाव के मौजूदा पैटर्न का परिणाम है और यह कि पर्यावरणीय नुकसान कई बार विनाशकारी हो सकता है, इसलिए स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों, किसानों और अन्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता के लिए भौगोलिक रूप से परिणाम अच्छे नहीं हो सकते, किसान और अन्य जो सीधे निर्भर करते हैं। वनों जंगलों, नदियों, झीलों, आर्द्रभूमि और महासागरों के उत्पादों पर। जिसके परिणामस्वरूप असमानता हाशिए पर है।

यह भी स्वीकार करते हुए कि सतत विकास और पारिस्थितिक तंत्र सहित पर्यावरण की सुरक्षा, मानव कल्याण और मानव अधिकारों के आनंद में योगदान करती है, जिसमें जीवन के अधिकार भी शामिल हैं, जैसे - शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम योग्य स्तर का आनंद लेने के लिए, पर्याप्त जीवन स्तर के लिए, पर्याप्त भोजन के लिए, स्वच्छ पेयजल, और स्वच्छता के लिए, आवास, और सांस्कृतिक अधिकार।

इसके विपरीत, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, प्राकृतिक संसाधनों के असंधारणीय प्रबंधन और उपयोग, वायु, भूमि और जल का प्रदूषण, रसायनों और अपशिष्टों का असंतुलित प्रबंधन, जैव विविधता के परिणामी नुकसान और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गिरावट को स्वीकार करते हुए पारिस्थितिक तंत्र एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के आनंद में हस्तक्षेप कर सकता है, और यह कि पर्यावरणीय क्षति के सभी मानव अधिकारों के प्रभावी आनंद के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।

यह स्वीकार करते हुए, कि जब दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा पर्यावरणीय क्षति के लिए मानवाधिकारों के प्रभाव को महसूस किया जाता है, जिसके परिणाम आबादी के उन हिस्सों में सबसे अधिक तीव्रता से महसूस किए जाते हैं, जो पहले से ही कमजोर परिस्थितियों में हैं, जिनमें महिलाएँ और लड़कियाँ।

जलवायु परिवर्तन और भूमि पर अपनी विशेष रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा मान्यता प्राप्त जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन के अवसरों को बढ़ाने के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए महिलाओं और स्वदेशी लोगों के अधिकारों के महत्व को याद करते हुए,

सशस्त्र संघर्ष और A/HRC/46/L.6/Rev.1 3 संघर्ष के बाद के संदर्भों की स्थितियों में प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट के अन्य रूपों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने, और कम करने की मांग से होने वाले लाभों को पहचानना, जिसके लिए बच्चों, महिलाओं, लड़कियों, युवाओं, विकलांग व्यक्तियों, वृद्ध व्यक्तियों, स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों, शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और प्रवासियों सहित कमजोर परिस्थितियों में व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों के प्रभावी आनंद के लिए उत्पन्न खतरों पर, अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना,

यह भी स्वीकार करते हुए कि सरकार और सार्वजनिक मामलों के संचालन में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सूचना प्राप्त करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता और एक प्रभावी उपाय के अधिकार सहित मानव अधिकारों का प्रयोग, एक स्वच्छ, स्वस्थ की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, सुरक्षित और टिकाऊ पर्यावरण।

21 मार्च 2019 के मानवाधिकार परिषद के संकल्प 40/11 की पुष्टि करते हुए, जिसमें परिषद ने पर्यावरणीय मामलों में काम करने वाले मानवाधिकार रक्षकों के योगदान को मान्यता दी, जिन्हें पर्यावरण मानवाधिकार रक्षकों के रूप में संदर्भित किया गया, मानव अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए सभी राज्यों से पर्यावरण मानवाधिकार रक्षकों सहित सभी व्यक्तियों के अधिकारों और सुरक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का आग्रह करता है, और व्यापार पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय और अन्य दोनों, सभी व्यावसायिक उद्यमों की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। मानवाधिकार, मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए, जिसमें जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता और मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा शामिल है, जिसमें पर्यावरण मानवाधिकार रक्षक भी शामिल हैं,

विश्व स्वास्थ्य संगठन "कोविड -19, से स्वस्थ वसूली के लिए घोषणापत्र" को नोट करते हुए, जिसका उद्देश्य कोरोनोवायरस बीमारी (COVID-19) महामारी के प्रभाव से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखने और पुनर्जीवित करने के लिए निवेश करते हुए एक स्वस्थ, निष्पक्ष और अधिक टिकाऊ दुनिया का निर्माण करना है।

एक स्वस्थ पर्यावरण से संबंधित मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले बच्चों और युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों द्वारा निभाई गई सकारात्मक, महत्वपूर्ण और वैध भूमिका को पहचानना, और आनंद से संबंधित मानवाधिकार दायित्वों के मुद्दे पर विशेष प्रतिवेदक के काम का स्वागत करना। बच्चों के साथ जुड़ने और परामर्श करने के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण, का होना,

लैंगिक समानता के महत्व को स्वीकार करते हुए, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट को संबोधित करने के लिए लिंग-प्रतिक्रियात्मक कार्यवाई, सशक्तिकरण, नेतृत्व, निर्णय लेने में महिलाओं और लड़कियों की सार्थक भागीदारी, और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधकों, नेताओं और रक्षकों और पर्यावरण की सुरक्षा में परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में महिलाएँ अपनी भूमिका निभाएँ।

वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, रसायनों के संपर्क में आने, जहरीले पदार्थों और कचरे, और जैव विविधता के नुकसान सहित पर्यावरणीय नुकसान के प्रभावों के प्रति बच्चों की विशेष भेद्यता को स्वीकार करते हुए, पर्यावरणीय नुकसान बच्चे के अधिकारों की एक विस्तृत शृंखला के पूर्ण आनंद में हस्तक्षेप कर सकता है। बच्चे के अधिकारों की एक विस्तृत शृंखला,

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जूनोटिक मूल के उभरते संक्रामक रोगों का बढ़ता जोखिम मानव कार्यों के कारण हो सकता है जो पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि जैव विविधता मानव अधिकारों की एक विस्तृत शृंखला के आनंद के लिए महत्वपूर्ण है, और चिंता व्यक्त करते हुए कि जैव विविधता का नुकसान मानवीय गतिविधियाँ उन अधिकारों के विस्तार के लिए खतरा हो सकती हैं, एवं स्वास्थ्य और आजीविका पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं,

इस बात की पुष्टि करते हुए, कि राज्यों का दायित्व है कि वे मानव अधिकारों का सम्मान करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें बढ़ावा दें, जिसमें पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए किए गए सभी कार्य शामिल हैं, और सभी के अधिकारों की रक्षा के उपाय करने के लिए जैसा कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समूहों में मान्यता प्राप्त है, और मानव पर रूपरेखा सिद्धांतों में परिलक्षित होता है, और उन लोगों के लिए भी अतिरिक्त उपाय जो विशेष रूप से पर्यावरणीय नुकसान के प्रति संवेदनशील हैं, किए जाने चाहिए,

यह देखते हुए कि 155 से अधिक राज्यों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के किसी न किसी रूप को अंतरराष्ट्रीय समझौतों या उनके राष्ट्रीय संविधानों, कानूनों या नीतियों में मान्यता दी है,

1. एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण से संबंधित मानवाधिकार दायित्वों के मुद्दे पर विशेष प्रतिवेदक द्वारा किए गए कार्यों का स्वागत करता है, जिसमें उनके जनादेश के कार्यान्वयन में व्यापक, पारदर्शी A/HRC/37/59, अनुबंध A/HRC/46/L.6/Rev.1 4 और प्रासंगिक हितधारकों, उनकी विषयगत रिपोर्टों, और देश के दौरों के उपक्रम के साथ आयोजित और समावेशी परामर्श निहित हैं।
2. मानवाधिकारों और वैश्विक जल संकट पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्टों की सराहना के साथ नोट करता है: जल प्रदूषण, पानी की कमी और पानी से संबंधित आपदाएँ और "मानव अधिकार एक स्वस्थ जीवमंडल पर निर्भर करते हैं" और उसमें दी गई सिफारिशों को भी नोट करता है।
3. मानव अधिकारों और पर्यावरण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के काम का स्वागत करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रबंधन समूह के लिए समर्थन और मानवाधिकारों के लिए महासचिव के कॉल टू एक्शन के लिए इसका समर्थन शामिल है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अन्य प्रमुख भागीदारों के साथ इसका सहयोग, बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के साथ इसकी भागीदारी, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मलेन,

संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, पर्यावरणीय कार्रवाई करते समय, जब उचित हो, मानवाधिकारों के लिए सम्मान और संरक्षण और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, और COVID-19 महामारी से एक समान और स्थायी प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के इसके प्रयास शामिल हैं।

4. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में, उच्चायुक्त के कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के कार्य की सराहना के साथ विशेष क्षेत्र में मानवाधिकारों के लिए महासचिव के आह्वान के तहत विकसित रणनीतिक हस्तक्षेपों में कार्यान्वयन।
5. तीन साल की अवधि के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के आनंद से संबंधित मानवाधिकार दायित्वों के मुद्दे पर विशेष प्रतिवेदक के जनादेश को नवीनीकृत करने का निर्णय लेता है;
6. जनादेश को पूरा करने में विशेष प्रतिवेदक से अनुरोध :
 - (a) विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित सरकारों, प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों, और अंतर सरकारी निकायों के परामर्श से एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के आनंद से संबंधित मानवाधिकार दायित्वों का अध्ययन जारी रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और प्रासंगिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते, मानवाधिकार तंत्र, स्थानीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, स्थानीय समुदायों और कमजोर परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों सहित स्वदेशी लोग और नागरिक समाज संगठन;
 - (b) मानवाधिकार दायित्वों और प्रतिबद्धताओं से संबंधित अच्छी प्रथाओं की पहचान, प्रचार और विचारों का आदान-प्रदान करना जारी रखना, जो पर्यावरण नीति निर्माण को सूचित, समर्थन और मजबूत करते हैं, विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, और उस संबंध में, जैसा कि उपयुक्त हो, पिछले जनादेश धारक द्वारा विस्तृत किए गए दस्तावेजों को प्रसारित करने और अपडेट करने पर विचार करना;
 - (c) एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के आनंद से संबंधित मानवाधिकार दायित्वों की पूर्ण प्राप्ति के लिए चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करने के लिए और सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में काम करना।
 - (d) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा और मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाई गई Stockholm घोषणा की पचासवीं वर्षगांठ से संबंधित घटनाओं सहित, जहाँ उपयुक्त हो, अंतर-सरकारी सम्मेलनों और जनादेश से संबंधित बैठकों में योगदान देना और भाग लेना जारी रखना।
 - (e) एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण का आनंद लेने से संबंधित मानवाधिकार दायित्वों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ एक संवाद विकसित करना, संपर्क करना और सहयोग करना; 3 A/HRC/46/28. 4 A/75/161. A/HRC/46/L.6/Rev.1 5
 - (f) देश का दौरा करना और राज्यों के निमंत्रणों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना;

- (g) महिलाओं और लड़कियों की विशेष स्थिति पर विचार करते हुए और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट को संबोधित करते समय लिंग-विशिष्ट भेदभाव और कमजोरियों की पहचान करते हुए, महिलाओं और लड़कियों के नेतृत्व को मजबूत करना और बढ़ावा देना , निर्णय लेने और उनके पूर्ण रूप से लिंग परिप्रेक्ष्य को लागू करना , समान और सार्थक भागीदारी, और अच्छी प्रथाओं को संबोधित करना , जहाँ महिलाएँ और लड़कियाँ पर्यावरण की सुरक्षा और प्रबंधन में परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं;
- (h) मानव अधिकार परिषद की अन्य विशेष प्रक्रियाओं और सहायक अंगों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सहित संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकायों, एजेंसियों, निधियों और कार्यक्रमों के साथ, अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए, निकट समन्वय में काम करना, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संधि निकाय और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन, और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते, प्रासंगिक क्षेत्रीय मानवाधिकार तंत्र, नागरिक समाज संगठन और शैक्षणिक संस्थान, एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों सहित अन्य हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए,
- (i) मानवाधिकार परिषद और महासभा को निष्कर्ष और सिफारिशों सहित एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
7. सभी राज्यों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निधियों और कार्यक्रमों, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों से विशेष प्रतिवेदक के साथ पूरी तरह से सहयोग करने का आह्वान करता है, जनादेश को पूरा करने के लिए उसे सक्षम करने के लिए जनादेश से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना शामिल है;
8. उच्चायुक्त से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता है कि विशेष प्रतिवेदक को आवश्यक संसाधन प्राप्त हों ताकि वह पूरी तरह से जनादेश का निर्वहन कर सके;
9. उच्चायुक्त कार्यालय के सहयोग से विशेष प्रतिवेदक से अनुरोध:
- (a) मानव अधिकार परिषद के 52वें सत्र से पहले, भविष्य की महामारियों की रोकथाम में मानवाधिकारों और पर्यावरण संरक्षण की भूमिका पर एक विशेषज्ञ संगोष्ठी का आयोजन करना;
- (b) संगोष्ठी में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए शैक्षणिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों और संधि निकायों सहित राज्यों और अन्य संबंधित हितधारकों को आमंत्रित करना;
- (c) संगोष्ठी में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निधियों और कार्यक्रमों, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों के प्रासंगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित करना;
- (d) मानवाधिकार परिषद को उसके 52वें सत्र में, आगे होने वाली कार्रवाई पर विचार करने के लिए उपर्युक्त संगोष्ठी पर एक सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें उससे उपजी सभी भी सिफारिशें शामिल हैं;
10. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, उच्चायुक्त के कार्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देता है। एजेंसियों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों, उनके संबंधित जनादेश के अनुसार, जिसमें नियमित रूप से ज्ञान और विचारों का

आदान-प्रदान करना और मानव अधिकारों की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा में तालमेल बनाना शामिल है, एक एकीकृत और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए;

11. विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नवंबर 2020 में वन हेल्थ हाई-लेवल एक्सपर्ट काउंसिल की शुरुआत को नोट करता है, ताकि विश्वसनीय संग्रह, वितरण और प्रचार किया जा सके। भविष्य के संकटों को दूर करने और नागरिकों को सूचित करने के लिए उचित निर्णय लेने में सार्वजनिक अधिकारियों की सहायता करने के लिए मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर वैज्ञानिक जानकारी
12. सभी राज्यों से स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण, संरक्षण और पुनर्स्थापना और मानव अधिकारों को लागू करके उनके स्थायी प्रबंधन और उपयोग को सुनिश्चित करने का आह्वान करता है- A/HRC/46/L.6/Rev.1 6 आधारित दृष्टिकोण जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में भागीदारी, समावेश, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देता है;
13. राज्यों की पार्टियों से जैविक विविधता पर सम्मेलनों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने और अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया;
14. सभी राज्यों से अपील है कि वे राष्ट्रीय उपायों को अपनाने और लागू करने पर विचार करें जो उन लोगों के अधिकारों का सम्मान और रक्षा करते हैं जो विशेष रूप से स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के नुकसान के प्रति संवेदनशील हैं;
15. पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले निर्णयों में उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर एहतियाती दृष्टिकोण लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करता है;
16. काम के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, मामले को जल्द करने का फैसला करता है।

जवाब, हवा में उड़ रहा है मेरे दोस्त :

(शीर्षक साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता Bob Dylan 2016, यदि आप गाना सुनना चाहते हैं, तो बस <https://youtu.be/G58XWF6B3AA> पर क्लिक करें)

नीचे दिए गए लेख में, **RGICS** के फेलो जीत सिंह का तर्क है कि **COVID-19** संकट पर्यावरणीय गिरावट के कारण हुआ था : महामारी और आर्थिक मंदी दोनों का एकल समाधान ग्रीन रिकवरी है। लेकिन कौन सुन रहा है?¹

जबकि SARS Cov-2 (COVID-19) की उत्पत्ति को जानने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन चल रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में स्वीकार किया है कि उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि SARS Cov-2 (COVID-19) में जूनोटिक स्रोत¹¹ हैं। पशुओं से फैलने वाले रोग। यह जूनोटिक प्रकोप अपने वैश्विक प्रसार, मृत्यु और इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के मामले में असाधारण रूप से बड़ा है।

¹¹ WHO COVID-19 स्थिति रिपोर्ट- 94, 23 अप्रैल, 2020, यहाँ से पहुँचा जा सकता है: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-siterep-94-covid-19.pdf?sfvrsn=b8304bf0_4_15.6.2020 को एक्सेस किया गया

COVID-19 महामारी ने 2020 में, वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक गंभीर संकीर्णता में SARS Cov-2 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों की महामारी और बंद होने के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.5 प्रतिशत की कमी आई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मंदी थी। इसके अलावा, इसने लाखों लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया¹²। इस संख्या को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, 2019 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगभग 87.55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था - जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास में 4.5 प्रतिशत की गिरावट वैश्विक स्तर पर खोए हुए आर्थिक उत्पादन में लगभग 3.94 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

भारत सरकार ने 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में कमी के अपने अनुमान को संशोधित कर 7.2 प्रतिशत कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इन आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने मई 2020 के महीने में एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कई अन्य नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वभाविक है, कि क्या ये नीतिगत निर्णय COVID-19 महामारी से उत्पन्न एक असाधारण संकट से निपटने के लिए सही दिशा में उठाया गया सही कदम हैं।

यहाँ विभिन्न विशेषज्ञों का मानना है, कि मौजूदा आर्थिक संकट पिछले बड़े संकटों से अलग है। जूनोटिक प्रकोप की उत्पत्ति बढ़ती मानवजनित गतिविधियों और दुनिया भर में भूमि उपयोग में बड़े पैमाने पर परिवर्तन में निहित है। इसलिए इस संकट में सतत आर्थिक विकास की तात्कालिकता भविष्य में इस तरह के किसी भी जूनोटिक प्रकोप को रोकने के लिए पहले से कहीं अधिक है। अप्रैल 2020 में आयोजित नवीनतम Petersberg जलवायु संवाद में भारत सहित 30 विभिन्न देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया, और वर्तमान संकट से हरित सुधार की वकालत की।¹³ इसी तरह IMF के मुख्य अर्थशास्त्री द्वारा हाल ही में मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में, सुश्री गीता गोपीनाथ ने IMF के सदस्य देशों से न्यायसंगत और स्थायी सुधार के लिए पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कहा है।¹⁴

इतिहास गवाह है कि 1973 और 1979 के तेल संकट, 1991 में USSR के पतन, 1997 के एशियाई वित्तीय संकट और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट सहित प्रमुख आर्थिक संकटों से उबरने के कारण आक्रामक औद्योगीकरण और विकास के कारण पर्यावरणीय गिरावट की दर में तेजी से वृद्धि हुई।¹⁵ इस तरह की

¹² <https://www.statista.com/topics/6139/covid-19-impact-on-the-global-economy/>

¹³ IISD, घोषणाएँ पर्याप्त नहीं हैं- महामारी के बाद के हरित भविष्य के लिए ठोस कदम, 12 मई, 2020, यहाँ से पहुँचा जा सकता है: <https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/announcements-are-not-enough-concrete-स्टेप्स-फॉर-पोस्ट-पांडेमिक-ग्रीन-फ्यूचर/>, 16 जून, 2020 को एक्सेस किया गया।

¹⁴ प्रिंट, लक्षित नीतियाँ, ऋण प्रबंधन, हरित अर्थव्यवस्थाएँ, 9 जून, 2020, यहाँ से एक्सेस किया गया: <https://theprint.in/economy/targeted-policies-managing-debt-green-economies-gita-gopinaths-covid-survival-गाइड/438472/>, 19 जून, 2020 को एक्सेस किया गया।

¹⁵ EPW एंगेज, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज और पर्यावरणीय स्थिरता, 08 मई, 2020, यहाँ से एक्सेस किया गया: <https://www.epw.in/engage/article/covid-19-crisis-Economic-stimulus-packages-and-environmental-sustainability>, 18 जून, 2020 को एक्सेस किया गया।

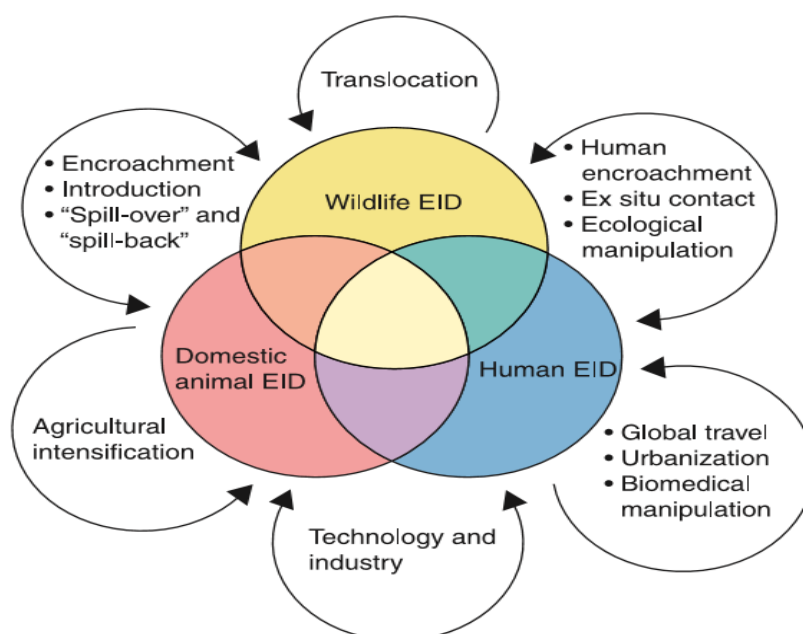
वृद्धि भविष्य में और अधिक जूनोटिक प्रकोपों के लिए जगह बनाएगी। इसलिए जरूरी है कि मौजूदा संकट से अलग तरीके से निपटा जाए।

पर्यावरणीय गिरावट और जूनोटिक रोगों का प्रसार

पिछली एक सदी से भी अधिक समय में सैकड़ों जूनोटिक रोग वन्यजीव जलाशयों से मानव बस्तियों तक पहुँच गए हैं। इनमें से कई बीमारियों ने आम लोगों के जीवन और आजीविका के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। कई जूनोज के लिए, हमारे पास स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं, कि वे वन्यजीव जलाशयों से कैसे निकले। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कुछ जूनोज के स्रोतों की जाँच की है, की किस तरह से वे मानव बस्तियों में फैल गए हैं। Ostfeld (2009) ने अपने एक अध्ययन में वेस्ट नाइल वायरस (WNV) और लाइम रोग (LD) नामक दो जूनोज के बारे में विभिन्न जंगली प्रजातियों के प्राकृतिक आवास के विनाश और बीमारियों के फैलने में मजबूत संबंध पाया। अध्ययन में पाया गया कि जैव विविधता के नुकसान के परिणामस्वरूप निवास स्थान का विनाश और विखंडन, प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और प्रत्यक्ष मानव शोषण हुआ।

2004 में अपनी रिपोर्ट में भूमि उपयोग परिवर्तन और रोग उभरने पर विशेषज्ञों के एक कार्यकारी समूह ने पाया कि मानवजनित भूमि उपयोग में परिवर्तन दुनिया भर में जूनोटिक प्रकोप (Jonathan A. Petz et al, 2004) की एक श्रृंखला को चलाते हैं। इसलिए, Ostfeld (2009) ने MNV और LD रोगों के अध्ययन पर आधारित अपने लेख में निष्कर्ष निकाला कि जैव विविधता की समृद्धि जूनोटिक रोगों के संचरण के खिलाफ एक बफर के रूप में काम करती है। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं, कि मानवजनित गतिविधियों ने जूनोटिक रोगों के प्रकोप को भड़काया है। निपाह वायरस सबसे पहले फल चमगादड़ से सुअरों में और सुअरों से इंसानों में पहुँचा। इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया में जंगल के विनाश के कारण फलों के चमगादड़ों का स्थानांतरण संक्रमित घोड़ों और फिर संक्रमित घोड़ों ने इसे एक बीमार घोड़े (Robin A Weiss et al, 2004) की जाँच करने वाले पशु चिकित्सक के पास भेज दिया।

चित्र : जूनोटिक स्पिलओवर और स्पिल-बैक के सामान्य कारण



स्रोत: Peter Daszak et al 2000

Peter Daszak के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनके मूल को समझने के लिए दुनिया में प्रमुख जूनोटिक प्रकोपों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने जूनोटिक प्रकोप के मूल से जुड़े कारकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का भी प्रयास किया। अध्ययन में पाया गया कि यूरोप में एवियन मलेरिया, इबोला, क्रिप्टोस्पोरिडिओसिस जैसी बीमारियों के उभरने के पीछे मानवीय गतिविधियाँ जैसे खेती का विस्तार, संक्रमित प्रजातियों का स्थानान्तरण, संक्रमित मेजबान का फैलाव, घरेलू जानवर से स्पिल-बैक और भोले जानवर का स्थानान्तरण कुछ प्रलेखित कारक हैं। और अफ्रीका में कैनाइन डिस्टेंपर ((Daszak, 2000) Dr. Jonathan A Patz के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समूह ने कार्रवाई योग्य नीतियों का सुझाव देने के लिए संक्रामक रोगों (जूनोटिक) के प्रकोप के प्रमुख चालकों को सूचीबद्ध किया। समूह ने पाया कि कृषि अतिक्रमण, वनों की कटाई, सड़क निर्माण, बांध निर्माण, सिंचाई, आर्द्रभूमि संशोधन, खनन, तेजी से शहरीकरण और तटीय क्षेत्र के क्षरण जैसी मानवजनित गतिविधियों के कारण ऐसे कारकों का एक समूह होता है जो फैलते हैं जो संक्रामक रोगों के स्पिलओवर और स्पिल-बैक को बढ़ाता है (Jonathan et al, 2000)।

उभरते संक्रामक रोगों के हॉटस्पॉट पर शुरुआती शोधों के विपरीत, इको हेल्थ एलायंस से जुड़े विशेषज्ञों के नवीनतम और ताजा शोध ने चेतावनी दी है कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र नए जूनोटिक प्रकोपों के उद्भव से सुरक्षित नहीं है (Allen et al 2017)। नए संक्रामक रोगों के उभरने की संभावना उन क्षेत्रों में भी अधिक होती है जहाँ मानवजनित गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर होती हैं। किसी भी क्षेत्र में नए जूनोटिक रोग "या तो 'स्पिलओवर' या क्रॉस-प्रजाति से या केवल भौगोलिक सीमा के विस्तार से नए या बदले हुए आवास हो सकते हैं"

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है, कि दुनिया भर में कई तरह से भूमि-उपयोग परिवर्तन पशु जन्य रोग (जूनोटिक) जनकों के प्रारंभ और पुनः उभरने से जुड़ा मुख्य कारक है। जूनोज की चुनौतियों पर 2003 में (WHO, FAO और OIE) के संयुक्त सम्मेलन ने जूनोटिक रोगजनकों के मूल और प्रसार से जुड़े कई सामाजिक, तकनीकी, पारिस्थितिक और माइक्रोबियल (सूक्ष्मजीव) कारकों को मान्यता दी। सम्मेलन ने इन कारकों को प्राथमिक जोखिम कारकों और प्रवर्धित जोखिम कारकों में विभाजित किया। सम्मेलन ने माना कि पर्यावरणीय कारक, जैसे - कृषि उत्पादन में बदलाव, पर्यावरण प्रदूषण, खपत पैटर्न में बदलाव, और मानव-पशु संपर्क को प्राथमिक जोखिम कारक (ओआईडी, 2004) के रूप में बढ़ाना।

Woolhouse et al (2005) ने अपने अध्ययन में जूनोटिक प्रकोप के लिए जोखिम कारकों को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया और जूनोटिक प्रकोप को भड़काने की उनकी क्षमता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता दी। उन्होंने यह भी पाया कि जूनोटिक संक्रमणों के उभरने और फिर से उभरने के लिए भूमि-उपयोग परिवर्तन सबसे प्रभावशाली कारक है। इसी तरह, इको हेल्थ एलायंस के नवीनतम अध्ययन ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि "वैश्विक रोग का जनक सीधे मानव-प्रेरित संचालनों से जुड़ा हुआ है, जैसे - कि भूमि-उपयोग परिवर्तन और दुनिया के अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच परस्पर क्रिया होना।¹⁶

¹⁶ इको हेल्थ एलायंस: <https://www.ecohealthalliance.org/2017/10/global-disease-hotspots-2-0>, 1.6.2020 को एक्सेस किया गया
PARIVESH, MoEF&CC, से एक्सेस किया गया: <https://parivesh.nic.in/compareanalytics.aspx>, 17 जून, 2020 को एक्सेस किया गया।

भारत में COVID महामारी के दौरान निरंतर पर्यावरणीय गिरावट

अप्रैल और मई 2020 में देशव्यापी तालाबंदी के दौरान विभिन्न मीडिया रिपोर्टों ने मानवजनित गतिविधियों की संख्या में हुई भारी कमी के कारण प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्जनन का दस्तावेजीकरण किया। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है, कि कई नदियों में पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है, वायु प्रदूषण में कमी और पूरे देश में वन्यजीवों और पक्षियों की आवाजाही में कमी के कारण आकाश में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जब विशेषज्ञ और आम नागरिक, सामान्य रूप से पर्यावरण में इन परिवर्तनों का स्वागत कर रहे थे, तब सरकार भारत में कुछ अत्यधिक जैव विविधता वाले वनों में अधिक मानवजनित गतिविधियों के लिए वन और वन्यजीव मंजूरी को मंजूरी देने में व्यस्त थी।

COVID-19 महामारी में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत चर्चाओं के केंद्र में सतत विकास के मुद्दों को लाया गया। और यह तर्क दिया गया है, कि न केवल अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने और भविष्य में अन्य जूनोटिक रोगों से बचाव के लिए हमें हरित क्रांति के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि, इसके विपरीत हमने भारत में पिछले ढाई महीनों में कई विवादास्पद और पारिस्थितिक रूप से प्रतिकूल विकास परियोजनाओं के लिए जल्दबाजी में कई पर्यावरणीय मंजूरी दे रखी हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2020 से 15 जून 2020 तक, भारत सरकार ने 249 परियोजनाओं को चरण-I में मंजूरी प्रदान की। इसी प्रकार, सरकार ने इस अवधि में 232 परियोजनाओं को चरण-II में मंजूरी प्रदान की है।¹⁷ कुछ प्रमुख पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने कुछ अत्यधिक विवादास्पद परियोजनाओं¹⁸ के लिए वन और वन्यजीव मंजूरी के निर्णय के लिए सरकार की आलोचना भी की है। गोवा में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य में अरुणाचल प्रदेश में इतालवी जल विद्युत परियोजना, और असम में देहिंग पाकई हाथी रिजर्व में कोयला खनन उनमें से ही कुछ हैं।

इतालवी पनबिजली परियोजना, अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में हिमालयी क्षेत्र के सबसे जैव-विविध क्षेत्रों में से एक में 1150.08 हेक्टेयर भूमि और 2.78 लाख से अधिक पेड़ों को गिराने की बजाए मोड़ना चाहती है। जबकि यह परियोजना लगभग 100 परिवारों को विस्थापित भी करेगी, और यह कई अन्य लोगों को परोक्ष रूप से प्रभावित करेगी। इसके अलावा भी इस परियोजना से जैव विविधता संपन्न क्षेत्र को खतरा होगा।

वन सलाहकार समिति (FAC) के अनुरोध पर भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया, कि प्रस्तावित परियोजना तितलियों की 159 प्रजातियों, मकड़ियों की 113 प्रजातियों, गंधकों की 11 प्रजातियों, के आवास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। सरीसृपों (रेंगने वाले जीव) की 31 प्रजातियाँ, पक्षियों की 230 प्रजातियाँ, और स्तनधारी जीवों की 21 प्रजातियाँ भी इससे प्रभावित होंगी। यह परियोजना पौधों की 413 प्रजातियों को भी संकट में डाल देगी¹⁹। प्रस्तावित स्थल

¹⁷ PARIVESH, MoEF&CC, Accessed from: <https://parivesh.nic.in/compareanalytics.aspx>, Accessed on June 17, 2020.

¹⁸ The Week, Environmentalists question clearances given during COVID-19 lockdown, Accessed from: <https://www.theweek.in/news/india/2020/05/13/environmentalists-question-clearances-given-during-covid-19-lockdown.html> Accessed on June 15, 2020.

¹⁹ PARIVESH, MoEF&CC, Minutes of the meeting of the forest advisory committee held on April 23, 2020, Accessed from: http://forestsclearance.nic.in/writereaddata/FAC_Minutes/51111121912211FACminutes23April20_compressed.pdf, Accessed on June 16, 2020.

दिबांग वन्यजीव अभयारण्य से 10 से 14 किमी दूर है। इतालवी परियोजना के शुरू होने से अभयारण्य में रहने वाले बाघों के आवास भी खंडित हो जाएँगे। FAC ने 23 अप्रैल, 2020 को अपनी बैठक में परियोजना के लिए वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दी है; हालाँकि, इसने केंद्रीय बिजली मंत्रालय से परियोजना की प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए भी कहा है, क्योंकि इसमें पहले ही 6 साल से अधिक की देरी हो चुकी है।

उत्तर-पूर्वी कोयला क्षेत्र (एनईसी) असम में देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व में अपनी कोयला खदान के अवैध विस्तार के लिए विवाद में था। कोयला खनन का विस्तार उत्तर-पूर्वी भारत के इस वर्षावन में रहने वाले हाथियों के आवासों को खंडित कर देगा। कई विवादों के बावजूद, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ (NBWL) ने 24 अप्रैल, 2020 को अपनी बैठक में नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (उत्तर-पूर्वी कोयला क्षेत्र) द्वारा ओपनकास्ट कोयला खनन के विस्तार को मंजूरी दी। यह विस्तार 98.59 हेक्टेयर महत्वपूर्ण हाथियों के आवास के भूमि उपयोग को बदल देगा²⁰। इसी तरह, NBWL ने भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में तीन अलग-अलग विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

गोवा में ये दो आरक्षित वन जैव विविधता संपन्न पश्चिमी घाट वन का एक अभिन्न अंग हैं। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना, पारेषण लाइन बिछाना और मौजूदा रेलवे लाइन को दोगुना करना शामिल है। ये तीन परियोजनाएँ 134 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को परिवर्तित करेंगी जिसके परिणामस्वरूप बाघ, ढोल, माउस हिरण, पेंगोलिन, और कई अन्य वन्यजीव और पौधों की प्रजातियाँ जैसे वन्यजीव प्रजातियों के आवास का विखंडन और विनाश होगा²¹।

अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार चिंतित है। पिछले कुछ महीनों में वन क्षेत्र में लंबे समय से लंबित परियोजनाओं की मंजूरी को सरकार के अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास से उचित ठहराया जा सकता है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या इन उपायों से अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ तरीके से पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी?

भारत में पर्यावरण और विकास के बीच व्यापार का भविष्य

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण सहित सभी नई विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक अनिवार्य प्रक्रिया है। ईआईए का उद्देश्य प्रतिबंध लगाकर, और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके पर्यावरणीय लागत को कम करना है। 2006 में भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम ईआईए अधिसूचना ने ईआईए के दायरे में वृद्धि की, और कई परियोजनाओं को ईआईए अधिसूचना के दायरे में लाया गया। तब से नीतिगत कमियों को पूरा करने के लिए अधिसूचना में बाद में संशोधन किया गया। अब 2006 की ईआईए अधिसूचना में उन सभी संशोधनों को समेकित करने और कुछ और संशोधनों को शामिल करने के लिए, (एमओईएफएंडसीसी) पर्यावरण एवं वन मंत्रालयने मार्च 2020 में ईआईए अधिसूचना का एक नया मसौदा जारी किया है। मसौदा, टिप्पणियों

²⁰ The Wire, India's Environment Ministry Unlocked Many Protected Areas During the Lockdown, Accessed from: <https://science.thewire.in/uncategorised/indias-environment-ministry-unlocked-many-protected-areas-during-the-lockdown/>, Accessed on 15 June, 2020.

²¹ The Wire, India's Environment Ministry Unlocked Many Protected Areas During the Lockdown, Accessed from: <https://science.thewire.in/uncategorised/indias-environment-ministry-unlocked-many-protected-areas-during-the-lockdown/>, Accessed on 15 June, 2020.

और सुझावों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जा रहा है। हालांकि, विभिन्न पर्यावरणविदों ने सार्वजनिक परामर्श के लिए अधिसूचना जारी करने के समय पर सवाल उठाया है। विशेषज्ञों ने विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मसौदे में प्रस्तावित नए संशोधनों की भी आलोचना की है।

बाद के संशोधनों को समेकित करने और पर्यावरण विनियमन को और मजबूत करने के लिए 2006 की ईआईए अधिसूचना में संशोधन की अत्यधिक आवश्यकता है। जबकि 2006 के बाद प्रख्यापित सभी परिवर्तनों को समेकित करने के प्रयास के लिए नई मसौदा अधिसूचना की सराहना की जाती है, एक विकास परियोजना की पर्यावरणीय लागत को कम करने के लिए कई कमजोरियों के लिए भी इसकी आलोचना की जाती है। इन कमजोरियों का हमारे पर्यावरण, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन वार्ता से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों ने आगाह किया है, कि प्रस्तावित संशोधनों से मानवजनित गतिविधियों में तेजी आएगी जिसके परिणामस्वरूप वन और वन्यजीवों के आवास का तेजी से विनाश होगा।

इतिहास से हमें जानकारी मिलती है, कि दुनिया ने हर बड़े आर्थिक संकट के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रकृति और पर्यावरण के विनाश को तेज किया। शायद, किसी भी आर्थिक संकट से निपटने का यह सबसे आसान तरीका है। आज, जब पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की तलाश में है, तो अधिक से अधिक तेजी से पर्यावरणीय गिरावट की संभावना है। पिछले कुछ महीनों में अत्यधिक जैव-विविध क्षेत्रों में और उसके आसपास विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी दी गई है, जो यह संकेत देती है कि भारत आर्थिक पुनरुद्धार के पारंपरिक तरीके की ओर बढ़ रहा है। MoEF&CC द्वारा EIA नियमों में प्रस्तावित परिवर्तन आगे संकेत करते हैं, कि आगे आर्थिक विकास के नाम पर प्रकृति के अधिक विनाश की अनुमति दी जाएगी।

निष्कर्ष

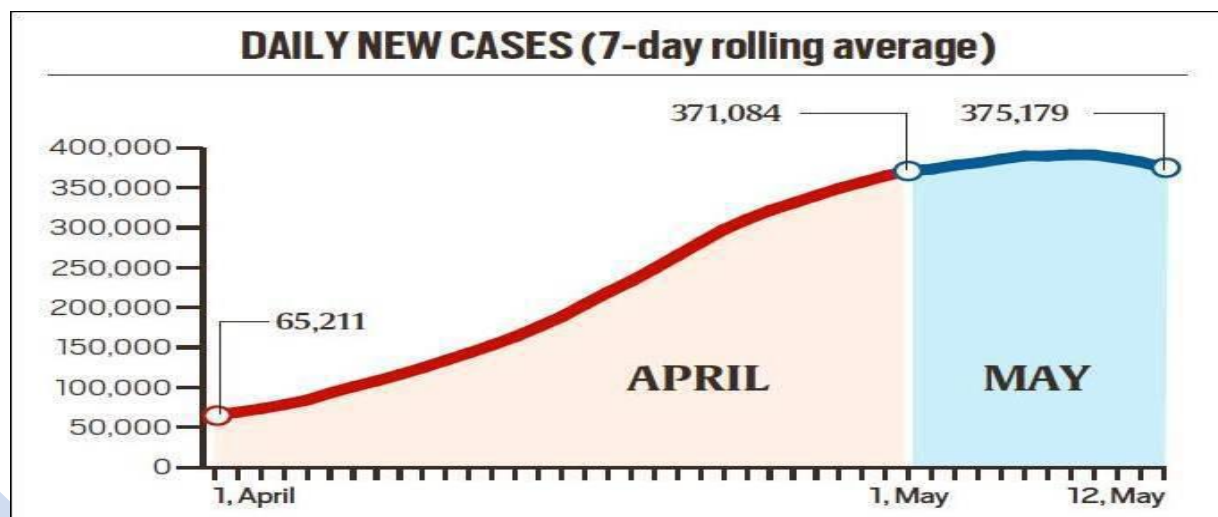
जूनोटिक SARS Cov-2 का वैश्विक प्रसारण और वैश्विक लॉकडाउन और औद्योगिक मंदी के कारण प्रकृति के पुनरुद्धार का मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन देने वाला संदेश है। इसलिए यह हम पर निर्भर करता है कि हम इससे कुछ सीखना चाहते हैं या नहीं। महामारी और इसके परिणाम यह जानने के लिए पर्याप्त हैं, कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन, जंगलों का विनाश, और विभिन्न उद्देश्यों के लिए वन्यजीवों के आवास के विखंडन से भविष्य में और अधिक जूनोटिक प्रकोप होंगे। COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकारों द्वारा अपनाए गए दुनिया भर में औद्योगिक उत्पादन के लॉकडाउन और मंदी के परिणामस्वरूप वन्यजीवों में उछाल आया और पर्यावरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। यह हमें यह भी बताता है कि हमारे दैनिक उत्पादन, खपत और आदतों के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हैं। यदि और कुछ नहीं, तो भविष्य में इस तरह के किसी भी जूनोटिक प्रकोप के खतरे से मुक्त होने के लिए, हमें अपने जीने और व्यवहार करने के तरीके को बदलना होगा।

संदर्भ

- Ostfeld, R.S. 2009, 'जैव विविधता हानि और जूनोटिक रोगजनकों का उदय, जर्नल संकलन, 2009, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इंफेक्शियस डिजीज, (CMI), 15 (सप्लीमेंट 1), 40-43
- Patz A. Jonathan, Peter Daszak, Gary M. Tabor, A. Alonso Aguirre, Mary Pearl, Jon Epstein, Nathan D. Wolfe, A. Marm Kilpatrick, Johannes Foufopoulos, David Molyneux, David J. Bradley, और भूमि उपयोग परिवर्तन और रोग उभरने पर कार्य समूह के सदस्य, 2004, "अस्वस्थ परिदृश्य: भूमि उपयोग परिवर्तन और संक्रामक रोग उभरने पर नीति अनुशंसाएँ" खंड 112 संख्या 10 जुलाई 2004 • पर्यावरणीय स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य
- Weiss Robin A और Anthony J McMichael, 2004, "संक्रामक रोगों के प्रारंभ में सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम कारक", प्रकृति चिकित्सा अनुपूरक, वॉल्यूम 10, संख्या 12, दिसंबर 2004
- Daszak Peter Daszak, Andrew A. Cunningham और Alex D. Hyatt, 2000 वन्यजीवों के उभरते संक्रामक रोग- जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा, विज्ञान कम्पास, वॉल्यूम 287, 21 जनवरी 2000
- Patz A. Jonathan, Peter Daszak, Gary M. Tabor, A. Alonso Aguirre, Mary Pearl, Jon Epstein, Nathan D. Wolfe, A. Marm Kilpatrick, Johannes Foufopoulos, David Molyneux, David J. Bradley, और भूमि उपयोग परिवर्तन और रोग उभरने पर कार्य समूह के सदस्य, 2004, अस्वस्थ परिदृश्य: भूमि उपयोग परिवर्तन और संक्रामक रोग उभरने पर नीति अनुशंसाएँ, वॉल्यूम 112, संख्या 10, जुलाई 2004 पर्यावरणीय स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य:
- Allen Toph, Kris A. Murray, Carlos Zambrana-Torrel, Stephen S. Morse, Carlo Rondinini, Moreno Di Marco, Nathan Breit, Kevin J. Olival & Peter Daszak, 2017, उभरते हुए जूनोटिक रोगों के वैश्विक हॉटस्पॉट और सहसंबंध, प्रकृति संचार डीओआई: 10.1038/एस41467-017-00923-8
- OIE (प्राथमिक जोखिम कारक) 2004, 'उभरते जूनोटिक रोगों पर WHO/FAO/OIE संयुक्त परामर्श की रिपोर्ट', मई 2004, यहाँ से एक्सेस किया गया: <https://www.oie.int/doc/ged/D5681.PDF>:
- Woolhouse. Mark E.J. and Sonya Gowtage-Sequeria, 2005, मेजबान रेंज और फिर से उभरने वाले रोगजनकों, उभरते संक्रामक रोग, संक्रामक रोग केंद्र

COVID-19 की दूसरी विनाशकारी लहर

यहाँ तक कि जब इस मुद्दे की योजना बनाई जा रही थी, तब तक भारत COVID-19 की दूसरी घातक लहर की चपेट में आ गया था। इस बार यह एक तीव्र और गंभीर पीड़ादायक थी - इसका संस्करण अत्यधिक संक्रामक था, और अक्सर सभी को एक ही छत के नीचे रहने के लिए मजबूर कर रहा था, क्योंकि कई परिवारों ने एक ही समय में अपने कई सदस्यों को बीमार होते और खोते देखा है। नीचे दिया गया ग्राफ दिखाता है, कि अखिल भारतीय COVID मामलों में अचानक कितनी वृद्धि हुई।²²



जैसे-जैसे COVID के मामले बढ़े, तो अस्पताल के बिस्तरों की, परीक्षण की, ऑक्सीजन की, अत्यधिक कमी होती गयी और बाद में मामलों में सुनवाई और श्मशान घाट के स्थान और समय की भी कमी होती गई, जिसके नतीजतन, कई सार्वजनिक पार्कों को भी श्मशान घाट में बदल दिया गया।²³



दिल में जलें चिताएँ

पिछले महीने, दिल्ली में श्मशान घाटों की पार्किंग पर बढ़ती चिताओं के ओवरफ्लो ने दुनिया भर तपिश ला दी। तब सामाजिक टिप्पणीकारों ने कवि को उद्धृत किया और कहा कि अप्रैल सबसे क्रूर महीना है। आज मेरे दिल में चिताएँ रो रही हैं, और यह महीना "मई" उन्हें जमीन पर पटक रहा है, निश्चित रूप से, मेरे लिए सबसे क्रूर है।

पिछले चार दिनों में, मैंने अपने 60 साल से कम उम्र के 3 करीबी घनिष्ट दोस्तों को खो दिया है, मेरा सबसे छोटा दोस्त सिर्फ 35 साल का था। आप देखिए, मेरे प्रत्येक मित्र मेरे लिए विशेष थे : वे वैकल्पिक दुनिया के निर्माण की बात करने वाले केवल वैकल्पिक लोग नहीं थे - वे हमारी असंभव रूप से बदसूरत दुनिया के ठीक बीच में एक वैकल्पिक दुनिया के निर्माण में लगे हुए थे। वे एक बेहतर भारत के अनदेखे, गुमनाम नायक थे। और वे सभी पीड़ित थे, नहीं, वायरस के नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने में भारत की अक्षमता के। पिछले साल, यहाँ तक कि एक महामारी के साथ, भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की तुलना में अपनी सेना पर 8 गुना अधिक खर्च किया। मैं क्रोध और उदासी, लाचारी और उदासी के बीच झूलता रहता हूँ।

कल रात, मुझे नींद नहीं आई, देश में लाखों लोगों की तरह। और मैं मानता हूँ कि हमें लाखों विशेषाधिकार प्राप्त हैं, मैंने अपने सभी सोशल मीडिया नेटवर्क पर घंटों भीख माँगते हुए बिताया, एक ऐसी वस्तु के लिए जो मेरे दोस्त की मदद कर सके, जो एक गहन देखभाल की टीम निगरानी में अपने

²³ <https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-in-pics-public-park-in-delhi-turns-into-cremation-ground-as-bodies-pile-up/381434>

जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। हमारा प्रयास हनुमान के उस प्रयास से कम नहीं था, जिसने लक्ष्मण को बचाने के लिए उस एक औषधीय जड़ी बूटी के लिए एक पूरा पहाड़ ही उठा लिया था। एक डॉक्टर, मेरे चचेरे भाई, ने जब मुझसे आग्रह किया, तो मैंने दोस्त के पूर्वानुमान पर एक नज़र डाली और अपना सिर हिला दिया। लेकिन मैं अडिग था। क्योंकि जब तक शरीर में श्वास है, तब तक जीने की आस है, और जब तक इच्छा है, तब तक आशा है। जोर से रोने के लिए, वह आदमी सिर्फ अपने तीसरे दशक में था और बिना किसी सह-रुग्णता के साथ फिट था। मैं हाई-स्कूल के दोस्तों के पास पहुँचा, जिनके संपर्क में रहने के लिए मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। लेकिन इस बार, मैं काफी समझदार था कि मैं यह पूर्वानुमान न बताऊँ कि मेरे दोस्त को माध्यमिक संक्रमण के कारण तेज बुखार था जो उसके सभी मुख्य अंगों को तबाह कर रहा था। एक उसी शहर के एक बड़े अस्पताल में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, जहाँ मेरा दोस्त लेटा था। "मैं एक युद्धक्षेत्र में हूँ," उसने आह भरी, "लेकिन मैं देखूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ!"

हम आशा और निराशा, आशा और लाचारी के बीच झूलते रहते हैं। मेरा एक पायलट मित्र उस रात बंगलौर से उड़ान में सामान लाने के लिए सहमत हुआ। परन्तु वह फ्लाइट कैंसिल हो गई। अगली सुबह हमें सामान पहुँचाने के लिए और अधिक स्वयंसेवकों ने दिल्ली से दूसरी एयरलाइनों की व्यवस्था की। आधी रात को मुझे खबर मिली कि मेरे दोस्त का निधन हो गया है। और जैसा कि मैं इन शब्दों को लिखता हूँ, एक सरकारी श्मशान में उनके पार्थिव शरीर की लपटें मुझे चाट रही हैं।

हमने जितने अपमान और अन्याय सहे हैं, निश्चित रूप से यह भी मायने रखता है : कि किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होना जिसे आप प्यार करते हैं और उस सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं जिसके वे हकदार हैं। लेकिन यह युद्ध की तरह है, मैं खुद को याद दिलाता हूँ। सभी युद्धों की तरह, ये यादृच्छिक, संवेदनहीन, अनावश्यक मौतें हैं। और जैसा कि दुनिया के सभी संघर्षग्रस्त इलाकों में, कश्मीर, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, इराक, मैं और सभी भारतीय परिवार अब उस अनिश्चितता के आतंक में जीते हैं, यह नहीं जानते कि आगे कौन प्रभावित होगा।

दिल्ली में लकड़ी के लिए मैला ढोने वालों की तरह, मैं अपने दिल के शेष संसाधनों को इकट्ठा करता, और उबारता और मेरे पास जो भी ताकत का भंडार बचा है उसे बचाने की कोशिश करता तभी मेरे भाई ने मुझे चेतावनी दी, कि भले ही मामलों की संख्या धीमी हो रही हो, लेकिन अगले दो हफ्तों में मौतों की संख्या में वृद्धि होना तय है। और हमारे ज्यादातर दोस्त और परिवार के सदस्य, विभिन्न शहरों में अस्पताल के बिस्तरों में, वेंटिलेटर के माध्यम से साँस ले रहे हैं। और हाँ, वे भाग्यशाली हैं जब तक कि किसी का भाग्य अभी भी कायम है।

लेखक की टिप्पणी : मैंने गुमनाम रहना चुना है, क्योंकि आखिरकार ये बात उस चिंता के बारे में नहीं है जिसे मुझे बनाना है, या वो कब्र जो मुझे खोदनी पड़ सकती है। यह सच है कि अब तक प्रत्येक भारतीय परिवार ने किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसकी वे परवाह करते थे, और हमें इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है।

गंगा के तट पर बेशुमार लाशें

यूपी में मौतों पर दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की कहानी²⁴

करीब एक किलोमीटर की दूरी में दबे शवों के बीच एक मीटर की दूरी भी नहीं है।

NL Team 18, द्वारा, मई, 2021

उत्तर प्रदेश के श्रृंगवेरपुर घाट की गंभीर स्थिति पर, यह आज के दिल्ली संस्करण में दैनिक भास्कर के पहले पन्ने का शीर्षक था। कहानी पिछले हफ्ते भास्कर की जमीनी रिपोर्ट के बाद की है, जहाँ उसके 30 पत्रकारों ने गंगा के 1140 किलोमीटर के हिस्से में "2,000 से अधिक शवों" के तैरते या दफन होने की सूचना दी थी।

आज की रिपोर्ट में, अखबार के पत्रकार अमरीश शुक्ला ने लिखा है, कि स्थिति इतनी भयावह थी कि "जहाँ तक नज़रें जाती थीं, वहाँ तक गंगा के किनारे फैली लाशों को देखा जा सकता था"। उन्होंने लिखा, कि "शवों के बीच एक मीटर की दूरी भी नहीं," उन्होंने लिखा, "एक किलोमीटर की दूरी में दफन।



स्रोत : <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fscience.thewire.in%2Fhealth%2Fbodies-float-down-the-ganga-as-nearly-4000-more-died-ऑफ-कोविड-19-इन-इंडिया%2F&psig=AOvVaw2jUqU79U1ZQc1BlvQiR9-o&ust=1621492243684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC369KP1fACFQAAAAAdAAAAABAD>

इस घाट पर प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद से अंतिम संस्कार लिए शवों को लाया जाता है। अंतिम संस्कार कराने वाले स्थानीय पुजारियों ने अखबार को बताया, कि जहाँ वे पहले एक दिन पहले आठ से 10 शव देखते थे, अब वे हर दिन "60 से 70" देख रहे हैं। "कुछ दिनों से 100 से अधिक लाशें आ रही हैं," अखबार ने एक पुजारी के हवाले से कहा। कि "यहाँ एक महीने में 4,000 से ज्यादा लाशें आ चुकी हैं।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से कोविड की दूसरी लहर शुरू हुई है, तब से घाट पर दाह संस्कार के लिए लकड़ियों की कमी देखी गई है। नतीजतन, लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा अत्यधिक कीमत वसूल की जा रही है।

²⁴ <https://www.newslandry.com/2021/05/18/uncountable-corpses-on-banks-of-ganga-dainik-bhaskars-front-page-story-on-deaths-in-up>

पारुल खाकर की गुजराती में कविता : शववाहिनी गंगा

इस भीषण कहानी के जवाब में प्रसिद्ध गुजराती कवयित्री पारुल खाकर ने 14 पंक्तियों की यह कविता लिखी है²⁵

इलियास शेख द्वारा हिंदी अनुवाद

एक साथ सब मुर्दे बोले सब कुछ चंगा-चंगा,
साहेब तुम्हारे राम-राज में शव वाहिनी-गंगा॥

खत्म-हुए शमशान तुम्हारे खत्म काष्ठ की बोरी,
थके हमारे कंधे सारे आँखे रह गई कोरी
दर-दर जाकर यमदूत खेले मौत का नाच बेढंगा,
साहेब तुम्हारे राम-राज में शव वाहिनी-गंगा॥

नित लगातार जलती चिंताएँ राहत माँगे पलभर,
नित लगातार टूटें चूड़ियाँ कुटती छाती घर-घर
देख लपटों को फिडल बजाते वह रे बिल्ला-रंगा
साहेब तुम्हारे राम-राज में शव वाहिनी-गंगा॥

साहेब तुम्हारे दिव्य-वस्त्र, दैदीप्य तुम्हारी ज्योति,
काश असलियत लोग समझते, हो तुम पत्थर ना मोती
हो हिम्मत तो आके बोलो, मेरा साहेब नंगा,
साहेब तुम्हारे राम-राज में शव वाहिनी-गंगा॥

कवि के साथ रहो!

खाखर द्वारा अपनी शव वाहिनी गंगा कविता पोस्ट करने के दो दिन बाद, भाजपा समर्थक ट्रोल ने घोषणा की, कि कवि ने अपने फेसबुक पेज से कविता को हटा दिया है। हालाँकि, द वायर इस बात की पुष्टि कर सकता है, कि कविता को हटाया नहीं गया है, हालाँकि अब उसका खाता निजी है, इसे केवल खाखर के मित्र ही देख सकते हैं। और खाखर के दोस्तों का कहना है कि वह निश्चिन्त है कि वह इसे वापस नहीं लेगी।

इस बीच, गुजराती लेखक मंडल (लेखकों का मंच), जिसमें गुजरात के एक हजार से अधिक लेखक और कवि शामिल हैं, ने उस कवि के समर्थन में बात की है, जिन्होंने बोलने की हिम्मत की है। गुजराती लेखक मंडल की अध्यक्ष और नवनिर्माण आंदोलन की पूर्व अध्यक्ष मानुषी जानी ने 13 मई को मंच को एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें भाजपा आईटी सेल के ट्रोलर्स को संक्षेप में संदर्भित किया गया था। पारुल खाकर अपनी कविता को लेकर अपशब्दों और जमकर ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं।

²⁵ <https://thewire.in/the-arts/parul-khakkar-gujarati-poem-ganga-bodies-covid>

मुद्दा -1 पर लौटें- हम इस समय में खुद से कैसे संबंधित हैं?

इन सब से कैसे उबरें? संगीत और कविता की उपचार शक्ति का प्रयोग करें :

इस चौंकाने वाली खबर से उबरने के लिए हम कहाँ जाएँ? हमें गंगा के आसपास की लोककथाओं और संस्कृति में भरपूर सहायता मिल सकती है। आइए हम आपको फिल्म सिद्धार्थ के उस गाने की ओर लिए चलते हैं जहाँ नाविक गाता है।

ओ नोदि रे एकती कोथा शुधई, बांग्ला गीत फिल्म सिद्धार्थ से²⁶

<https://gaana.com/song/o-nodire-ekti-kotha-shudhai>

Here's an English translation, courtesy Prof Somnath Ghosh:

इस गीत और संगीत के रचनाकार हैं हेमंत मुखोपाध्याय, और इसे हेमंत कुमार द्वारा मूल बांग्ला भाषा में गाया गया है और इसका अनुवाद प्रो. सोमनाथ घोष ने किया है।

हे नदी.....

मेरे पास पूछने के लिए केवल एक ही सवाल है,

हे नदी, आप कहाँ से हो?

क्या आपके सफ़र का कोई अंत नहीं है?

हे नदी!

आपका कोई संबंधी नहीं; कोई साथी नहीं

क्या इसलिए कि आपका कोई घरबार नहीं,

एक पल तुम उतार पर हो, एक और क्षण मैं तुम्हें पूरे ज्वार में देखता हूँ

आप कहाँ से हो? क्या आपके सफ़र का कोई अंत नहीं है?

हे नदी!

आप एक ठिकाना (रास्ता) छोड़ती हो, दूसरा बनाती हो

लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, न यह ठिकाना न वह

आप उनके लिए क्या करती हो?

मुझे अजनबी (झूठा) क्यों समझती हो?

क्या तुम्हारे पास अपने सुख-दुख मेरे साथ बाँटने का समय नहीं है?

हे नदी!

मुझे बस एक ही सवाल पूछना है... आप कहाँ से हो?

क्या आपके सफ़र का कोई अंत नहीं है?

²⁶ इस लिंक का आयोजन मसूद खान ने किया था :

https://www.smule.com/song/hemanta-mukhopadhyay-o-nodire-ekti-kotha-shudhai-karaoke-lyrics/672906952_1859648/arrangement

भूपेन हजारिका : - असम के प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका ने गंगा पर एक और गीत गाया है। यह स्पष्ट रूप से है क्योंकि गंगा को बांग्लादेश में माना जाता है, जहाँ गंगा की मुख्य नदी को पद्मा कहा जाता है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र की मुख्य वितरिका को जमुना कहा जाता है और दोनों एक दूसरे में बहती हैं और मेघना नदी का निर्माण करती हैं जो अंततः बंगाल की खाड़ी में बहती है।

ओ गंगा आमार माँ, भूपेन हजारिका द्वारा गाया गया

इसे सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें : <https://youtu.be/7WQCITNz31g>

गंगा का आकर्षण अखिल भारतीय है - सदियों से हजारों तीर्थयात्री गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए दक्षिण भारत से काशी आए हैं।

ॐॐॐ (गंगा) मधुसूदनन नायर की कविता मलयालम में

मधुसूदनन नायर द्वारा उनकी प्रसिद्ध मलयालम कविता का एक पाठ यहाँ दिया गया है :

<https://youtu.be/36Ut2k2rd4I>

क्षमा करें, हमें अंग्रेजी या हिंदी अनुवाद नहीं मिला। बस अपना "मल्लू" दोस्त बुलाओ और पूछो!

नदियाँ | कार्तिकेय खेत्रपाल द्वारा और केदारनाथ सिंह द्वारा पाठ किया गया

समकालीन हिंदी कवि केदारनाथ सिंह ने दरार की सदियों पुरानी थीम से कैसे निपटा है, इसके स्वाद को जानने के लिए, नीचे दिए गए लिंक को देखें, सौजन्य से नई धारा रेडियो YouTube पर

<https://youtu.be/36vI8ik5LJg>

या, हम अपने प्राचीन काल के ज्ञान के लिए गहरी खुदाई कर सकते हैं : स्नान मंत्र

यदि हम और भी अधिक सहायता चाहते हैं तो आइए हम श्रद्धेय स्नान मंत्र में गंगा के इस आह्वान को सुनें, जिसका उल्लेख ऊपर कार्तिकेय खेत्रपाल ने भी किया है।

नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें :

<https://gaana.com/song/snaan-mantra-4>

हम सद्भावना संकलन के इस अंक को हम दो व्यक्तियों को श्रद्धांजलि के साथ समाप्त करते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन उस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया, जिसमें वे विश्वास करते थे।

स्वामी सानंद : भविष्य द्रष्टा, सिद्ध पुरुष, जिन्होंने गंगा को बचाने के लिए मौत का उपवास किया

फैजी नूर अहमद द्वारा 11 अक्टूबर, 2018²⁷



गंगा नदी को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरणविद् स्वामी सानंद का गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गंगा के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के विरोध में 22 जून से अनशन पर बैठे 86 वर्षीय साधु ने 9 अक्टूबर से सभी प्रकार के तरल पदार्थों का सेवन बंद कर दिया था। बुधवार को हरिद्वार प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती एम्स में भर्ती कराया था।

गंगापुत्र' के नाम से मशहूर जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई में हमेशा सबसे आगे रहे हैं। मुजफ्फरनगर के कांधला जिले में किसानों के परिवार में जन्मे स्वामी सानंद ने आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पहले सदस्य सचिव थे। अमेरिका में बर्कले से पीएचडी के साथ, वह दो दशकों तक आईआईटी कानपुर में सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख थे। उनकी तरह, उनके छात्र पर्यावरण सक्रियता के क्षेत्र में प्रमुख नाम बन गए। अनिल अग्रवाल, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, दिल्ली के संस्थापक ने अपने इतने शानदार करियर के बावजूद, उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग चुना और 2014 में वाराणसी के श्री विद्या मठ में संन्यास ग्रहण किया।

स्वामी सानंद ने गंगा के संरक्षण के लिए एक कानून की मांग करते हुए हरिद्वार में मातृ सदन आश्रम में उपवास किया; कुछ अन्य लोग भी अपने तरीके से इस कारण की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह, गंगा को मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए उत्तराखंड के गौमुख से पश्चिम बंगाल के गंगासागर तक 105 दिनों की यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महीने के राफिटिंग अभियान पर हैं। गंगा के तट पर स्थित मातृ सदन आश्रम इस उद्देश्य के लिए

²⁷ <https://www.theweek.in/leisure/society/2018/10/11/swami-sanand-the-seer-who-fasted-death-save-ganga.html>

कई निरंतर प्रयासों का साक्षी रहा है। आंदोलन ने अतीत में अपने दो संन्यासियों के जीवन का दावा किया था, एक स्वामी निगमानंद थे जिनकी 2011 में उपवास से मृत्यु हो गई थी।

अपनी अंतिम सांस तक एक पर्यावरण कार्यकर्ता, स्वामी सानंद ने 2008 में अपना पहला उपवास किया था, जिसके बाद 2009 और 2010 में भैरों घाटी, लोहारी नागपाला और पाला मनेरी में जलविद्युत परियोजनाओं के खिलाफ भी उपवास किया, और उन सभी को रोकने में सक्षम हो गए थे। वास्तव में, लोहारी नागपाला में परियोजना लगभग पूरी हो गई थी, जब पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 में इसे खत्म कर दिया था। उन्होंने सरकार से भागीरथी नदी के 125 किमी हिस्से को एक पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा था। 2012 में जब उन्होंने चौथा अनशन किया तो उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 2013 में, उन्होंने अपने पांचवें उपवास के कारण 15 दिन जेल में बिताए।

स्वामी सानंद का मानना था कि नरेंद्र मोदी सरकार नदी संरक्षण के लिए एक कदम आगे बढ़ेगी जैसा कि गंगा के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना से स्पष्ट था। हालाँकि, उनकी धारणा बदल गई और उन्होंने दावा किया कि सरकार की हर कार्रवाई कॉर्पोरेट्स के लिए एक फायदेमंद है, और सत्ता में बैठे लोगों ने गंगा के लिए कुछ नहीं किया।

5 अगस्त, 2018 को पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में स्वामी सानंद ने निम्नलिखित चार मांगों को सूचीबद्ध किया :

1. गंगा महासभा द्वारा 2012 में तैयार किए गए विधेयक का मसौदा सरकार को तत्काल संसद में चर्चा के लिए लाना चाहिए और इसे पारित कराना चाहिए। यदि विधेयक पारित नहीं होता है, तो मसौदे के अध्याय 1 के अनुच्छेद 1 से 9 तक को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा लागू किया जाना चाहिए।
2. सरकार को अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और गंगा नदियों पर सभी निर्माणाधीन और प्रस्तावित बिजली परियोजनाओं को रद्द करना चाहिए।
3. विशेष रूप से हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में वनों की कटाई, वध और सभी प्रकार की खनन गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए।
4. केवल नदी के हित में कार्य करने की शपथ के तहत प्रधानमंत्री द्वारा नामित 20 सदस्यों के साथ एक गंगा भक्त परिषद का अस्थायी रूप से गठन किया जाना चाहिए।

स्वामी सानंद ने गंगा की पवित्रता और उपचार गुणों में इसके समर्थन के लिए आईआईटी कानपुर में अपने शोध के साथ दृढ़ विश्वास बनाए रखा। उनका विचार था कि कार्याकल्प केवल शुद्धिकरण का सुझाव नहीं देता है, बल्कि पानी के प्रवाह, गुणवत्ता और स्पष्टता को उसके मूल रूप में बहाल करने का सुझाव देता है। उन्होंने कहा था कि सरकार ने गंगा की सफाई में देरी की है उनकी नमामि गंगे योजना के तहत सिर्फ सीवरेंज बनाकर वोट बैंक का फायदा उठाने की मंशा है। उन्होंने केंद्रीय जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी की आंदोलन को समाप्त करने की याचिका को खारिज कर दिया था क्योंकि उन्हें गडकरी के आश्वासनों में कुछ भी ठोस आश्वासन नहीं मिला था।

और अब, सिद्धपुरुष की मृत्यु के साथ, गंगा ने अपने एक सबसे मजबूत योद्धा को खो दिया है।

श्री सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धांजलि : 9 जनवरी 1927 - 21 मई 2021

वयोवृद्ध पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा का COVID से निधन

प्रख्यात गांधीवादी पर्यावरणविद् और चिपको व टिहरी बांध आंदोलनों के नेता सुंदरलाल बहुगुणा अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जिसे निभाना मुश्किल होगा।



प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बताया, वयोवृद्ध पर्यावरणविद् और चिपको आंदोलन के वास्तुकार सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई, 2021 को निधन हो गया। नई कोरोना वायरस बीमारी (COVID-19) से पीड़ित होने के बाद उन्हें उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था।

बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेताओं में से एक थे, जो हिमालय में जंगलों के संरक्षण के लिए लड़ रहे थे। चिपको का अर्थ है 'आलिंगन' या 'पेड़ को गले लगाने वाले' और यह विशाल आंदोलन एक विकेन्द्रीकृत आंदोलन था जिसमें कई नेता आमतौर पर ग्रामीण महिलाएँ थीं। अक्सर, वे खुद को पेड़ों से बाँध लेते थे ताकि लकड़हारे जंगलों को काट न सकें। इन कार्यों ने विनाश को धीमा कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वनों की कटाई को जनता के ध्यान में लाए।

1981-1983 तक, सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय के पार 5,000 किलोमीटर के मार्च का नेतृत्व किया, जो दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक बैठक के साथ समाप्त हुआ, जिन्होंने तब हिमालय के जंगलों के कुछ क्षेत्रों को पेड़ की कटाई से बचाने के लिए कानून पारित किया था। सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध परियोजना का विरोध करने और भारत की नदियों की रक्षा करने के आंदोलन में भी अग्रणी थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और गरीबों के अधिकारों के लिए भी काम किया। उनके तरीके गांधीवादी थे, शांतिपूर्ण प्रतिरोध और अहिंसा का उपयोग करना।

चिपको आंदोलन को 1987 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, " भारत के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, बहाली और पारिस्थितिक रूप से ध्वनि उपयोग के प्रति समर्पण के लिए।"

“क्या हैं, जंगल के उपकार

मिट्टी, पानी और बयार

मिट्टी, पानी और बयार

जिंदा रहने के आधार”